सुविचार
जो मन पूर्वाग्रह तथा द्वंद्व से मुक्त है, वही देख सकता है कि सत्य क्या है।
-जे. कृष्णमूर्ति

Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज Published from Ranchi

Ranchi ●Saturday, 25 April 2026 ●Year : 05 ●Issue : 100 ●Ranchi Edition ●Page : 12 ●Price : ₹3 ●www.thephotonnews.com E-Paper : epaper.thephotonnews.com

Sree leela's Film Still In Early Phase
12

राघव चड्ढा सहित 'आप' के 7 सांसदों ने छोड़ी पार्टी, भाजपा में जाने की घोषणा

AGENCY NEW DELHI : पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा के सात सदस्यों ने अपने दल की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में जाने का फैसला किया है। पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल एवं संदीप पाठक ने शुक्रवार को संविधान क्लब में संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। चड्ढा ने कहा, राज्यसभा में 'आप' के 10 सांसद हैं, उनमें से दो तिहाई से ज्यादा हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और सुबह हमने राज्यसभा के सभापति को हस्ताक्षरित पत्र और दस्तावेज सौंप दिए। उनमें से 3 यहां आपके सामने हैं। हमारे अलावा हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल हैं। राघव चड्ढा ने कहा, 'आप' जिसे मैंने

अपने खून-पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, अब अपने सिद्धांतों, मूल्यों और बुनियादी नैतिकताओं से भटक गई है। अब यह पार्टी देश के हित में नहीं, बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम करती है। पिछले कुछ सालों से, मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूं। संसद के उच्च सदन में आम आदमी पार्टी के उपनेता रहे चड्ढा ने कहा, हमने फैसला किया है कि हम राज्यसभा में पार्टी के दो तिहाई सदस्य भारत के संविधान के प्रावधानों का पालन करेंगे और (एक पार्टी के रूप में) खुद को भाजपा में विलय करेंगे।

ट्रेजरी घोटाला : सीआईडी की नौ सदस्यीय टीम ने शुरू की जांच

आईजी पंकज कंबोज की अध्यक्षता में बनाई गई है विशेष जांच टीम

वेतन समेत कई मदों में अवैध निकासी के पूरे नेटवर्क को किया जाएगा उजागर

PHOTON NEWS RANCHI : प्रदेश में ट्रेजरी घोटाले को लेकर अब जांच ने गति पकड़ ली है। सरकार की अनुमति के बाद झारखंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्मेंट (सीआईडी) ने इस पूरे मामले को टेकअप कर लिया है। गौरतलब है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी पंकज कंबोज की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है। टीम ने विधिवत तरीके से जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में जांच दल की ओर से जानकारी दी गई है। बताया गया है कि यह जांच ट्रेजरी से वेतन समेत कई मद में हुई अवैध निकासी के पूरे नेटवर्क को उजागर करने पर केंद्रित होगी।

उच्च स्तरीय समिति का दस्तावेज मांगने पर जोर

वेतन मद से फर्जी निकासी के मामले में जांच तेज करते हुए उच्च स्तरीय समिति ने दस्तावेजों की मांग पर जोर दिया है। शुक्रवार को वरीय आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में गठित समिति ने हजारीबाग जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और कोषागार पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पूरे मामले की समीक्षा की। समिति ने पुलिस विभाग द्वारा जारी वेतन मद की राशि और उसकी निकासी से जुड़े सभी आवश्यक कागजात तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही उप-महालेखाकार को भी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है, ताकि अध्ययन के बाद समय पर फील्ड विजिट की जा सके। समिति में वर्ष 2011 से 2026 तक यानी 15 सालों के कागजात मांगें हैं।

कई आरोपियों को भेजा जा चुका है जेल

बता दें कि इस घोटाले की परतें उस वक्त खुलनी शुरू हुईं, जब बोकारो और हजारीबाग जिलों में ट्रेजरी से संदिग्ध निकासी के मामले सामने आए। जांच में पाया गया कि वेतन मद के नाम पर फर्जी तरीके से पैसे निकाले गए। इस खुलासे के बाद वित्त विभाग और संबंधित ट्रेजरी कार्यालयों में हड़कंप मच गया था। विभागीय स्तर पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कई अधिकारियों और कर्मचारियों को चिह्नित किया गया। कुछ को निलंबित किया गया, जबकि कई के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। कई आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। साथ ही ट्रेजरी सिस्टम में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ी रोकने के लिए निगरानी भी बढ़ाई गई है।

शुरूआती संकेतों में बड़े स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। खास बात यह कि वित्त विभाग के स्तर से आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी भी मामले की जांच कर रही है। अब सीईडी की एसआईटी इस मामले की तह तक जाकर यह पता लगाएगी कि इस घोटाले में कौन-कौन लोग शामिल हैं। इसके साथ पैसे की निकासी किस प्रक्रिया के तहत हुई और इसमें किस स्तर तक मिलीभगत रही।

SHARE		
संसेक्स	:	76,664.21
निफ्टी	:	23,897.95

SARAFA		
सोना	:	14,170
चांदी	:	265.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने रास में दिया नया नोटिस

NEW DELHI : शुक्रवार को विपक्षी दलों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के संदर्भ में राज्यसभा को नया नोटिस सौंपा और उन पर सत्तारूढ़ दल के साथ निकटता सहित कई आरोप लगाए। संसद के उच्च सदन के 73 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला यह नोटिस राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को दिया गया है। विपक्ष ने इससे पहले संसद के दोनों सदनों में कुमार के खिलाफ नोटिस दिया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था।

सीजेआई ने पश्चिम बंगाल में भारी मतदान होने पर जताई संतुष्टि

NEW DELHI : पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 92 फीसद से ज्यादा मतदान होने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि भारत का एक नागरिक होने के नाते मैं वोटिंग प्रतिशत देखकर बहुत खुश हूं। जब लोग वोट डालते हैं, तो लोकतंत्र मजबूत होता है। जब लोग अपने वोट की अहमियत समझने लगते हैं, तो वो हिंसा में शामिल नहीं होते। जस्टिस बागची ने भी कहा कि हिंसा की कोई बड़ी घटना भी नहीं हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 92 फीसद मतदान ऐतिहासिक है। कुछ चुनिंदा घटनाओं को छोड़ दिया जाए, तो चुनाव शांतिपूर्ण ही रहा है। केंद्रीय बलों ने भी शानदार काम किया है।

हथियारबंद अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर बैंक के कर्मचारी से खुलवाया लॉकर

हजारीबाग में बैंक से तीन किलो सोना व चार लाख कैश की लूट

बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बरही शाखा में शाम 4 बजे दिया घटना को अंजाम

शाखा प्रबंधक अजय राम को भी अपराधियों ने मारपीट कर किया घायल

PHOTON NEWS HAZARIBAG : हजारीबाग जिला स्थित बरही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में शुक्रवार को करीब तीन किलो सोना और लगभग 4 लाख रुपये नकद की लूट हो गई। बताया जाता है कि अपराधियों ने लॉकर लूट लिए। घटना को शाम चार बजे अंजाम दिया गया है। एसपी अमन कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। एसपी ने बताया कि अपराधी बैंक से करीब 3 किलो सोना और चार लाख कैश ले गए हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बैंक में चार अपराधी घुसे थे। चारों ने अपने चेहरे को छिपा लिया था। एक ने हेलमेट पहन रखा था, एक मास्क में था और अन्य दो ने गमछे से चेहरा ढंका था। सभी के हाथों में देसी पिस्टल थे। बैंक में घुसते ही उन्होंने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद कर्मचारियों को डराकर लॉकर खुलवाया और उसमें रखा सारा सोना निकाल लिया। इसके साथ ही काउंटर से नकद राशि भी समेट ली। लूट के बाद अपराधियों ने बैंक को बाहर से बंद कर दिया, ताकि तुरंत कोई उनका पीछा न कर सके और आराम से फरार हो गए। घटना के बाद बैंककर्मियों ने किसी तरह बाहर निकलकर पुलिस को सूचना दी।

बताया जा रहा है कि संबंधित बैंक शाखा करीब 7-8 माह पहले ही शुरू हुई थी। इतनी बड़ी वारदात का इतने कम समय में हो जाना बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है।

- बैंक में घुसे चारों अपराधियों ने छिपा रखा था अपना चेहरा, सबके हाथ में था देसी पिस्टल
- लूट के बाद अपराधियों ने बैंक को बाहर से कर दिया बंद, फिर हो गए फरार
- पुलिस बोली- जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को किया जाएगा गिरफ्तार

तुरंत मौके पर पहुंचे डीएसपी अजीत कुमार विमल

सूचना मिलते ही बरही के डीएसपी अजीत कुमार विमल और थाना प्रभारी विनोद कुमार मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

बाइक से आए थे अपराधी

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चारों अपराधी दो बाइक से बैंक तक पहुंचे थे। वे ग्राहक बनकर अंदर घुसे और पहले खाता खुलवाने की बात कही। इसके बाद कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगे। शाखा प्रबंधक अजय राम को भी अपराधियों ने मारपीट कर घायल कर दिया।

अंदरूनी जानकारी पर शक

बैंक अधिकारियों व पुलिस को इस बात से हैरानी है कि अपराधियों को अंदरुनी जानकारी कैसे हुई। वे जिस तरह से अंदर घुसते ही लॉकर तक पहुंचे, उससे सभी को आश्चर्य हो रहा है। इससे यह शक भी गहरा रहा है कि बैंक का ही कोई स्टाफ अपराधियों से मिला तो नहीं था।

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह-सह-मुखिया सम्मेलन में शामिल हुए सीएम

गांवों के विकास के लिए नहीं होने दी जाएगी पैसों की कमी : हेमंत

PHOTON NEWS RANCHI : शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य का समग्र विकास गांवों के विकास पर निर्भर है और सरकार गांवों को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। गांव के विकास में पैसों की कमी नहीं होने दी जाएगी। वे शुक्रवार को हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव में आयोजित मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह- सह-मुखिया सम्मेलन 2026 (दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल) को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री और अतिथियों ने राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित उत्कृष्ट ग्राम पंचायत, श्रेष्ठ ग्रामसभा, स्वच्छ एवं स्वस्थ पंचायत समिति और जिला परिषद श्रेणी के विजेताओं को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि ग्रामीणों के सबसे करीब होते हैं और उनकी कार्यकुशलता से ही विकास की दिशा तय होती है। गांव राज्य की जड़ हैं, जब जड़ मजबूत होगी, तभी पूरा तंत्र मजबूत होगा। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही मुख्य लक्ष्य है और इसके लिए पंचायत स्तर पर लगातार शिविर लगाकर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को परिवर्तनकारी पहल बताते हुए कहा कि इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और बेहतर काम करने वालों को पहचान मिलेगी। करोड़ों रुपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण सरकार की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंचायतों के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उपलब्ध बजट का सही उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिए विभाग को स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था, जब लोग राशन कार्ड लेकर भटकते थे, लेकिन बीते वर्षों में व्यवस्था में सुधार हुआ है और आज राज्य में भूख से मौत की स्थिति नहीं है।

- सरकार गांवों को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कर रही काम
- सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही मुख्य लक्ष्य
- पंचायत प्रोत्साहन योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित

पंचायतों को हजारों करोड़ की दी जा रही सहायता : दीपिका

इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पंचायतों को बड़े पैमाने पर विकास कार्यों के लिए राशि दी गई है। 15वें वित्त आयोग के तहत टाइड फंड में 412 करोड़ रुपये और अनटाइड फंड में 555 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। जल्द ही टाइड फंड में 410 करोड़ रुपये और अनटाइड फंड में 272 करोड़ रुपये और जारी किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग से भी करीब 600 करोड़ रुपये पंचायतों को मिलने जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि यह राशि गांवों के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि अब मुखियाओं के पास योजनाओं को जमीन पर उतारने का सुनहरा अवसर है।

29 साल पुराने अलकतरा घोटाले में चार दोषियों को 3-3 साल की सजा

- सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
- साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को किया गया बरी

PHOTON NEWS RANCHI : करीब तीन दशक पुराने बहुचर्चित अलकतरा घोटाला से जुड़ा फैसला अब आया है। साल 1997 से जुड़े इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया और तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही सभी दोषियों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। ट्रांसपोर्टर विनय कुमार सिन्हा, राजकुमार राय, आशीष मैती और रंजन प्रधान को सजा सुनाई गई है। साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों- एसके दास, एसएम औरंगजेब और एनसी प्रसाद को बरी कर दिया गया है। ट्रायल के दौरान दो आरोपियों- मो. इसहाक और भरत प्रसाद गुप्ता की मौत हो चुकी है। सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक खुशबू जायसवाल ने पक्ष रखा। अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए 35 गवाहों की गवाही और दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में पेश किए।

रांची के जगन्नाथ मंदिर में गार्ड की हत्या खुली मिली दानपेटी, सभी अपराधी अरेस्ट

PHOTON NEWS RANCHI : राजधानी रांची में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में गुरुवार की देर वहां तैनात गार्ड की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। मृतक की पहचान बिरसा मुंडा के रूप में हुई है, जो मंदिर में सुरक्षा गार्ड के रूप में लंबे समय से कार्यरत था। मौके पर दानपेटी खुली मिली। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करेगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को घेरकर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की सुबह जब श्रद्धालु पूजा करने मंदिर पहुंचे, तब उन्होंने परिसर में गार्ड का शव पड़ा देखा। इसके बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि गार्ड मंदिर में सो रहा था। उसी बीच अज्ञात चोर मंदिर में घुसे और गार्ड की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद चोर ने मंदिर में रखी दानपेटी का ताला तोड़ा और उसमें रखे पैसे लेकर भाग गए।

सीसीटीवी फुटेज से पुलिस के हत्थे चढ़े अपराधी

उपलब्धि

रोजगार, बुनियादी ढांचे के विकास और वित्तीय समावेशन में हुई वृद्धि

अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे रही बैंकिंग सेक्टर की मजबूती

PHOTON NEWS, RESEARCH DESK : अर्थशास्त्रियों के अनुसार, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बैंकिंग सेक्टर की कमजोरी या विसंगति पूरी व्यवस्था पर नकारात्मक असर डालती है। मूलभूत रूप से यह सेक्टर पूंजी निर्माण, आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए बैकबोन के रूप में कार्य करता है। बैंकिंग प्रणाली लोगों की बचत को सुरक्षित जमा के रूप में स्वीकार कर उसे व्यवसायों और उद्योगों को लोन यानी कर्ज के माध्यम से उत्पादक निवेश में बदलती है। इससे रोजगार, बुनियादी ढांचा विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और इंडियन बैंक एसोसिएशन के हालिया सर्वे में यह जानकारी दी गई है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर फिलहाल मजबूत स्थिति में है। यह मजबूती अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे रही है। सर्वे जनवरी से फरवरी 2026 के बीच किया गया था। इसमें 24 बैंकों ने हिस्सा लिया था। सर्वे की रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले की अपेक्षा बैंकों की हालत बेहतर हो रही है और आगे भी इसमें सुधार जारी रहने की उम्मीद है। इस मजबूती का कारण अच्छी एसेट क्वालिटी (कम खराब लोन), मजबूत पूंजी, और रिटेल व छोटे कारोबार में बढ़ती कर्ज की मांग है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर के ग्रोथ को लेकर माहौल सकारात्मक है। इसकी वजह मजबूत बैलेंस शीट और अर्थव्यवस्था में स्थिर गतिविधियां भी हैं।

लोन की डिमांड में बढ़ोतरी, एसेट क्वालिटी और क्रेडिट मांग से मिल रहा सपोर्ट

- » व्यवस्थित तरीके से पूरी की जा रही रिटेल व छोटे कारोबार में कर्ज की जरूरत
- » फिक्की और इंडियन बैंक एसोसिएशन के हालिया सर्वे में विस्तार से दी गई है जानकारी
- » आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ को लेकर सकारात्मक माहौल का मिल रहा संकेत
- » सशक्त बैलेंस शीट और इकोनॉमी में स्थिर गतिविधियों का भी मिल रहा बड़ा सहारा

- फिलहाल संतुलित है मौजूदा मौद्रिक नीति, बड़े बदलाव की संभावना बहुत कम

बढी सरकारी बैंकों की रुचि

सर्वे में यह जानकारी दी गई है कि मौजूदा मौद्रिक नीति (ब्याज दर से जुड़ी नीति) फिलहाल संतुलित है और इसमें बड़ा बदलाव होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि कुछ सहकारी बैंकों ने ब्याज दर में हल्की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। बैंकों को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में कर्ज की मांग बढ़ती रहेगी, खासकर रिटेल और छोटे-मध्यम उद्योगों से। सरकारी बैंक भविष्य को लेकर ज्यादा भरोसेमंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी एसेट क्वालिटी सुधरी है और कॉरपोरेट लोन में रुचि बढ़ रही है।

उद्योगों को सरकार का सपोर्ट

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि निजी बैंक थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि विदेशी बैंक कॉरपोरेट सेक्टर में निवेश को लेकर संतुलित रुख अपना रहे हैं। सर्वे में करीब 46% लोगों का मानना है कि इस साल नॉन-फूड क्रेडिट ग्रोथ 11% से 13% के बीच रह सकता है। रिटेल लोन भी बैंकिंग सेक्टर के लिए एक मजबूत सहारा बना रहेगा। छोटे और मझोले उद्योगों के लिए लोन की मांग भी तेज रहने की उम्मीद है, क्योंकि इस सेक्टर में व्यापार बढ़ रहा है और सरकार का भी इसे सपोर्ट मिल रहा है।

ट्रंप के पास जंग जारी रखने के लिए बचे सिर्फ छह दिन

WASHINGTON : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान से जंग जारी रखने के लिए सिर्फ छह दिन बचे हैं। अमेरिकी संविधान के अनुसार, किसी भी युद्ध को 60 दिनों में संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। यहां भी ट्रंप ने खेल किया। युद्ध 28 फरवरी को छेड़ा, संसद को 2 मार्च को सूचित किया। अब एक मई से पहले उन्हें संसद से युद्ध की मंजूरी लेनी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप संसद का सामना नहीं करना चाहते हैं। 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रंप के 53 सांसद हैं, जबकि विपक्षी कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 47 सदस्य हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के ही लगभग 10 सांसद ईरान युद्ध के विरोध में आवाज उठा चुके हैं, जबकि विपक्षी डेमोक्रेट एकजुट रहने वाले हैं।

पेयजल घोटाले के अभियुक्त के साथ मारपीट की होगी सीबीआई जांच

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की याचिका

PHOTON NEWS RANCHI : शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पेयजल घोटाले के अभियुक्त संतोष कुमार के साथ हुई मारपीट के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका पर सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ में हुई। इससे पहले इस मामले की सुनवाई की तिथि 13 अप्रैल को निर्धारित थी। लेकिन, राज्य सरकार के अनुरोध पर कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी थी। गौरतलब है कि पेयजल घोटाले के अभियुक्त संतोष कुमार ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) के अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने ईडी के कार्यालय को घेरकर जांच शुरू की थी। ईडी की ओर से घोटाले के अभियुक्त द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सीबीआई को संतोष कुमार द्वारा दर्ज प्राथमिकी की जांच करने का आदेश दिया था।

धनबाद में आधी रात को जमींदोज हो गए कई घर, चीख-पुकार से दहल उठे लोग

कतरास के सोनारडीह में 21 से ज्यादा घर हुए ध्वस्त, परिवारों को बेलगड़िया किया जा रहा शिफ्ट

PHOTON NEWS DHANBAD: धनबाद स्थित सोनारडीह (कतरास) के टंडाबारी में गुरुवार की देर रात प्रकृति और खनन के गठजोड़ ने ऐसा खौफनाक मंजर दिखाया, जिसे देख रूह कांप उठी। धरती फटने से देखते ही देखते आधी बस्ती जमींदोज हो गई। अचानक हुए भू-धंसान के कारण पूरी की पूरी बस्ती करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में समा गई। पूर्व प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया के घर सहित दर्जनों घरों का नामोनिशान मिट गया। आधी रात के सन्नाटे के बीच धरती के फटने की आवाज ने लोगों को इस कदर डरा दिया कि लोग गहरी नींद से जागकर अपने मासूम बच्चों को कलेजे से चिपकाकर नंगे पैर जान बचाकर भागने लगे।

भू-धंसान से क्षतिग्रस्त मकान

बताया जाता है कि देर रात जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी अचानक जमीन हिलने लगी और देखते ही देखते पक्के मकान ताश के पत्तों की तरह ढहकर पाताल में समाने लगे। अचानक आई इस आपदा और भागदौड़ के दौरान कई लोग मलबे की चपेट में आने व गिरने से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार दिया गया है। एक घर के भीतर खड़ी कार भी मलबे के साथ जमीन के भीतर धंस गई। जान बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे लोगों की चीख-पुकार सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। अपना सब कुछ खो चुके परिवारों का कहना है कि उन्होंने जीवन भर की कमाई से ये घर बनाए थे, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने एक पल में मिट्टी में मिला दिया।

जिला पुलिस और सीआईएसएफ तैनात : तनावपूर्ण स्थिति और लोगों के भारी आक्रोश को देखते हुए घटनास्थल पर जिला पुलिस और सीआईएसएफ की टीम तैनात कर दी गई है। पुलिस उग्र ग्रामीणों को समझाने और यातायात सुचारू करने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि, प्रभावित परिवारों ने दोटूक कह दिया है कि जब तक सुरक्षित पुनर्वास और उचित मुआवजे का लिखित आश्वासन नहीं मिलता, वे पीछे नहीं हटेंगे। पूरे क्षेत्र में इस वक्त मातमी सन्नाटा और भारी दहशत का माहौल है।

एनएच-32 कर दिया जाम, फूटा गुस्सा

घटना के बाद विस्थापित और प्रभावित लोगों का आक्रोश बीसीसीएल प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने शुक्रवार को सुरक्षा और पुनर्वास की मांग को लेकर एनएच-32 को पूरी तरह जाम कर दिया। सड़क पर धरने पर बैठे ग्रामीणों का आरोप है कि बीसीसीएल की अनदेखी के कारण आज दर्जनों परिवार सड़क पर आ गए हैं। बताया जाता है कि प्रशासन को पूर्व में भी धंसान की चेतावनी दी गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

ट्रक ने स्कूटी में मारी टक्कर मां व उसके दो बच्चों की मौत

घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त स्कूटी व ट्रक

LOHARDAGA : कुडू-रांची मुख्य पथ (एनएच-39) पर लोहरदगा थाना क्षेत्र के ढुलुवाखुंटा के पास ट्रक और स्कूटी के बीच हुई टक्कर में दो की मौके पर मौत हो गई है। जबकि एक महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना में कुल चार लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। बताया जाता है कि 407 वाहन में सरकारी शराब लोड था। यह रांची से कुडू की ओर आ रहा था। इसी बीच वाहन कुडू की ओर से रांची की तरफ जा रही स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में स्कूटी सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसे इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की भी मौत हो गई। मृतकों में मां तथा उसके दो पुत्र हैं। जबकि, चार लोग घायल हैं। घटना के बाद दो घंटे तक हाइवे जाम रहा। काफी समझा-बुझाकर पुलिस ने सड़क जाम हटाया। घटना में तीन वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, इसमें शराब लदा मालवाहक वाहन, स्कूटी व एक कार शामिल हैं।

BRIEF NEWS

रोड जाम मामले के सभी आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

DEOGHAR : देवघर जिले के बहुचर्चित रिखिया थाना कांड में जिला न्यायालय ने शुक्रवार को 2019 में रोड जाम मामले के सभी 19 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। इस फैसले के साथ लंबे समय से चल रहे इस मामले का पटाक्षेप हो गया। यह मामला लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें बैजनाथपुर चौक पर ईवीएम से भरे एक ट्रक को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि इस दौरान वाहन को रोकने, लूटपाट करने और नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं हुई थीं। हालांकि, अदालत में सुनवाई के दौरान यह साबित नहीं हो सका कि किसी वाहन की लूट हुई थी या उसे कोई क्षति पहुंचाई गई थी।

गड्ढे में गिरी बकरी लदी पिकअप वैन, एक घायल

PALAMU : पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोसाईडीह गांव में शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे बकरी लदा एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गया। इस हादसे में वाहन पर सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अन्य सवारों को हल्की चोटें आई हैं। घायल की पहचान गोसाईडीह निवासी सुंदर यादव के 30 वर्षीय पुत्र प्रभु यादव के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि प्रभु यादव सुबह अपने गांव से पिकअप पर बकरी लादकर बेचने के लिए संडा गांव जा रहा था। इसी दौरान घर से करीब आधा किलोमीटर दूर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया। घटना के बाद परिजनों ने आनन-फानन घायल को छतरपुर के अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज-अस्पताल (एमएमसीएच) रेफर कर दिया। एमएमसीएच में इलाज के बावजूद उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

करोड़ों की जमीन बेचने में कोडरमा की महिला गिरफ्तार

KODERMA : जमीन फजीर्वाड़े के एक बड़े मामले में राजस्थान पुलिस ने कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र से एक महिला को हिरासत में लिया है। शुक्रवार को राजस्थान के चुरू जिले के राजगढ़ थाने की पुलिस टीम तिलैया पहुंची और अड्डी बांग्ला निवासी संगीता देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए तिलैया थाना ले आयी। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले के संबंध में राजगढ़ थाने के एसआई धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि संगीता देवी, महावीर राजगढ़िया की पत्नी हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने चुरू जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में करोड़ों रुपए की जमीन को फर्जी कागजात के आधार पर बेहद कम कीमत पर बेच दिया। इस मामले में राजगढ़ के वार्ड पार्षद महेंद्र जनोंदिया को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस के अनुसार, इस पूरे मामले की शुरूआत अक्टूबर 2022 में हुई, जब राजगढ़ निवासी राजेश कुमार ने जमीन फजीर्वाड़े की शिकायत दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि 1337.67 वर्ग फीट के एक प्लॉट, जिसकी वास्तविक कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपए थी, को गलत दस्तावेजों के जरिए बेचा गया। तफ्तीश के दौरान यह खुलासा हुआ कि महेंद्र जनोंदिया और मनोज कुमार ने मिलकर जमीन के असली मालिक की पहचान खोजी और पता लगाया कि यह संपत्ति मंगलचंद धनोदिया के परिवार से जुड़ी है। परिवार में केवल संगीता नाम की एक महिला के जीवित होने की जानकारी मिली, जिसके पति का नाम महावीर है। इसके बाद दोनों ने ऐसी महिला की तलाश शुरू की, जिसका नाम संगीता हो और पति का नाम महावीर हो। इसी क्रम में वर्ष 2022 में संगीता देवी राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थस्थल सालासर धाम दर्शन के लिए गई थी, जहां उसकी मुलाकात मनोज से हुई। बातचीत में जैसे ही संगीता ने अपना और अपने पति का नाम बताया, मनोज और उसके सहयोगियों ने इस महिला का उपयोग कर फजीर्वाड़े की योजना बना ली। इसके बाद संगीता को लालच देकर एक फर्जी वंशावली तैयार की गई, जिसमें उन्हें मंगलचंद की विधवा बहू दिखाया गया। फिर पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से जमीन मनोज के नाम कर दी गई। पुलिस के अनुसार, मनोज ने इस काम के लिए संगीता को 11 लाख रुपये दिए, जबकि संगीता का दावा है कि उसे मात्र 11 हजार रुपये ही मिले। जांच में यह भी सामने आया कि मनोज ने बाद में यह जमीन राजेश कुमार को बेच दी। जब राजेश इस जमीन को आगे बेचने गए, तब निबंधन कार्यालय में फजीर्वाड़े का खुलासा हुआ। इसके बाद राजेश ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जांच में एक और बड़ा खुलासा यह हुआ कि संगीता देवी पहले भी वर्ष 2015 में इसी तरह के एक मामले में शामिल रही हैं, जिसमें करीब एक करोड़ रुपये की जमीन फर्जी तरीके से बेची गई थी। उस मामले में भी उनके खिलाफ केस दर्ज है और मामला फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित है।

सड़क दुर्घटना में शिक्षक की मौत ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर

HAZARIBAG : हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा थाना क्षेत्र के सकरेज फोरलेन पर शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में बाइक सवार शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गयपहाड़ी निवासी चंद्रशेखर आजाद (पिता-गुलाबचंद महतो) के रूप में हुई है। वह चतरा जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सोकी में प्रधानाध्यापक थे। जानकारी के अनुसार, चंद्रशेखर आजाद रोज की तरह शुक्रवार को सुबह में बाइक से स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान सकरेज फोरलेन पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही शिक्षक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही बरकट्ठा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर लिया है और ट्रेलर के चालक की तलाश में जुट गई है। घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं, विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है।

चंद्रशेखर आजाद

कुडू में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

आक्रोशित ग्रामीणों ने किया रोड जाम, पुलिस-प्रशासन के समझाने के बाद माने

PHOTON NEWS LOHARDAGA : लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र अंतर्गत ढुलुवा खूंटा के पास एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में किशोर भगत (32), उसकी मां बिशुन भगताइन (53) और किशोर का चचेरा भाई निरंजन उरांव (26) शामिल हैं। सभी कुडू थाना क्षेत्र के रोनिहा कोलसिमरी निवासी थे। बताया जाता है कि कुडू थाना क्षेत्र के रोनिहा कोलसिमरी निवासी किशोर भगत, बिशुन भगताइन और निरंजन उरांव कुडू से रांची के मांडर स्थित अस्पताल जा रहे थे। यहां वे अस्पताल में भर्ती अपने एक रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान रांची की ओर से आ रहे 407 ट्रक ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में किशोर भगत और निरंजन उरांव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बिशुन भगताइन ने लोहरदगा सदर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। ट्रक में अंग्रेजी शराब लदी हुई थी और वह रांची से डाल्टनगंज की ओर जा रहा था। ट्रक में सवार बिनत मुंडा, विकास मिंज और सिंकू राम को चोट आई है। तीनों रांची के गांधीनगर कांके रोड के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है।

कुडू में दुर्घटनाग्रस्त वाहन

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ देर के लिए रोड जाम कर दिया था।

सूचना मिलते ही कुडू के सीओ संतोष उरांव और थाना प्रभारी अजीत कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटाया। प्रशासन द्वारा मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए तत्काल सहायता राशि प्रदान की गई और अन्य सरकारी सहायता जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। लगभग एक घंटे बाद जाम हटाया गया।

पुरुष करते थे डकैती, महिलाएं छिपाती थीं गहने, सात किए गए गिरफ्तार

रजरप्पा डकैती कांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए झारखंड और बिहार के कई ठिकानों पर हुई थी छापेमारी

PHOTON NEWS RAMGARH : पुलिस को चकमा देने के लिए अपराधी गिरोह तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हालांकि लगातार प्रयासों से पुलिस अपराधियों को पकड़ने में सफल हो जाती है। इसी कड़ी में रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत चितरपुर बाजार की जेवर दुकान में 21 अप्रैल को हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल दो महिलाओं सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही दुकान से लूटे गए 180 पीस से अधिक जेवर भी बरामद कर लिए हैं। शुक्रवार को एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने प्रेसवार्ता में बताया कि डकैती कांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए झारखंड और बिहार के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी में कुजू ओपी के बरकट्ठी गांव निवासी सुभानी अंसारी उर्फ ललका, बिहार के नालंदा जिला के मनीष कुमार, उसकी पत्नी रीना देवी, नूरसराय थाने के गणपुरा गांव निवासी चंद्रावती देवी, रांची जिले के पंडरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हेसल निवासी आनंद कुमार, न्यू विधानसभा थाना क्षेत्र के मुड़मा निवासी अरबाज अंसारी और दीपा टोली निवासी नसरुल्लाह अंसारी उर्फ राजा को पकड़ा गया है।

गिरफ्त में आरोपी व जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी

गिरोह के सुभानी का है आपराधिक इतिहास, 15 मामले हैं दर्ज : एसपी ने बताया कि गिरफ्तार सुभानी अंसारी उर्फ ललका का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ कुजू, मांडू, रजरप्पा, पेटरवार के अलावा जमशेदपुर रेल थाने में भी प्राथमिकी पहले से दर्ज है। उसके खिलाफ अभी तक कुल 15 मामले थाने और कोर्ट में चल रहे हैं।

लूटे गए जेवर को छिपाकर रखती थीं महिलाएं : रामगढ़ में डाका डालने पहुंचा गिरोह काफी शातिर था। इस गिरोह की महिला सदस्य लूटे गए जेवर को छिपाने का काम करती थीं। रामगढ़ में डकैती करने के बाद गिरोह के कई सदस्य फरार हो गए थे। उन लोगों ने सभी जेवर चंद्रावती देवी और रीना देवी के हाथों में थमा दिया था। पुलिस ने जमीन में गाड़े हुए जेवर भी बरामद कर लिए हैं।

शादी समारोह में जा रहे युवक की गोली मारकर की हत्या

DEOGHAR : देवघर जिले में गुरुवार को देर रात मोहनपुर थाना क्षेत्र के जयपुर मोड़ के पास अज्ञात हमलावरों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान राजन कुमार लाल (26) के रूप में की गई। वह रिखिया थाना क्षेत्र के बिहाई गांव का रहने वाला था। वह गुरुवार को शाम करीब 5.30 बजे घर से बहन के यहां शादी समारोह में जाने की बात कहकर निकला था। देर रात करीब 11 बजे परिवार को सूचना मिली कि उसे गोली मार दी गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक, राजन अपने साले राहुल कुमार और अन्य लोगों के साथ शादी समारोह में जा रहा था। रास्ते में जयपुर मोड़ के पास चाय पीने के लिए रुकने के दौरान एक अज्ञात वाहन से पहुंचे हमलावरों ने बिना किसी विवाद के सीधे उसके सीने में गोली दाग दी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल राजन को तुरंत देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि हमलावर घटना के बाद अपनी पिस्टल मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए थे। घटनास्थल से हथियार बरामद होने के बाद पुलिस को जांच में महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है। मृतक के पिता दिनेश लाल ने मोहनपुर थाना में आवेदन देकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों के अनुसार, आपसी रंजिश, पुरानी दुश्मनी समेत अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

प्रशासन 70 परीक्षा केंद्रों पर झारखंड पात्रता परीक्षा-2024 कल, 23 हजार 634 अभ्यर्थी होंगे शामिल, आईआरआईएस अटेंडेंस सिस्टम से होगी जांच

आंख की पुतली से होगी परीक्षार्थियों की पहचान

PHOTON NEWS DHANBAD : जिले के 70 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को झारखंड पात्रता परीक्षा-2024 होगी, जिसमें 23 हजार 634 परीक्षार्थी शामिल होंगे। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए शुक्रवार को उपायुक्त आदित्य रंजन तथा एसएसपी प्रभात कुमार की उपस्थिति में न्यू टाउन हॉल में सभी स्टैटिक दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दंडाधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। उपायुक्त ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। किसी भी परीक्षा केंद्र के आसपास भीड़ नहीं होनी चाहिए। सभी दंडाधिकारियों को उनके साथ टैग पुलिस पदाधिकारी के साथ समन्वय बनाने, परीक्षा के दौरान कोई समस्या आने पर वरीय पदाधिकारियों को सूचित करने, परीक्षा केंद्र पर कोई अव्यवस्था उत्पन्न न होने देने, अपने दायित्व का अच्छे से निर्वहन करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि यह महत्वपूर्ण परीक्षा है। कोई कोताही नहीं बरतें। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश एवं निकास के लिए सिंगल गेट सिस्टम की व्यवस्था रहेगी। इस बार आईआरआईएस अटेंडेंस सिस्टम से अभ्यर्थियों की पहचान की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि आईआरआईएस अटेंडेंस सिस्टम अत्यंत सुरक्षित, स्पर्शरहित बायोमीट्रिक समाधान है, जो आंखों की पुतली के चारों ओर स्थित रंगीन वलय (आइरिस) में मौजूद विशिष्ट पैटर्न की उच्च-रिजोल्यूशन वाली छवियां कैप्चर करके व्यक्ति की पहचान प्रमाणित करता है। आइरिस का पैटर्न जीवन भर स्थिर रहता है और इसे कॉपी करना लगभग असंभव है। परीक्षार्थी अपनी सही सीट पर बैठे, यह भी सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक को संबोधित करते प्रशासनिक पदाधिकारी व न्यू टाउन हॉल में उपस्थित दंडाधिकारी व केंद्र अधीक्षक

केवल पेन-पेंसिल ही ले जा सकेंगे परीक्षार्थी

उपायुक्त ले कहा कि कोई भी परीक्षार्थी, परीक्षक या परीक्षा में लगा अन्य कोई व्यक्ति, परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी, कैलकुलेटर, पेजर, चिप, कंप्यूटर को प्रभावित करने वाले उपकरण सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। अभ्यर्थी केवल लेखन सामग्री लेकर ही प्रवेश करेंगे। परीक्षा के अवसर पर सभी परीक्षा केंद्रों तथा स्ट्रांग रूम परिसर के पास किसी भी मीडिया प्रतिनिधि, पत्रकार, छायाकार अथवा अन्य मीडिया कर्मियों का प्रवेश पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। एसएसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्धारित समय से पूर्व ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया। प्रश्नपत्रों का मिलान कर लेने, दंडाधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखने, परीक्षा केंद्र पर सतर्क रहने एवं कंट्रोल रूम के साथ सीधे संपर्क में रहने की हिदायत दी। एडीएम हेमा प्रसाद ने परीक्षा से संबंधित समय सारिणी, सीटिंग प्लान, विभिन्न प्रपत्र को भरने, अभ्यर्थियों का प्रवेश एवं निकास, दंडाधिकारियों का कर्तव्य, फ्लाइंग स्क्वायड एवं पुलिस पदाधिकारी का दायित्व, प्रश्नपत्रों का वितरण, गश्ती व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर दिशा निर्देश दिया।

परीक्षा के दौरान सक्रिय रहेंगे दो नियंत्रण कक्ष

झारखंड पात्रता परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक संचालित की जाएगी। परीक्षा के दौरान आयोग के नियंत्रण कक्ष के साथ जिला नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 0326 - 2311807 तथा 112 एवं आयोग के नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 9431301636, 9431301419 प्रभावी रहेगा। इसी बैठक में 3 मई को जिले के सात सेंटर पर होने वाली यूजी (नीट) परीक्षा को लेकर नीट के सिटी को-ऑर्डिनेटर शैलेंद्र शर्मा ने परीक्षा से संबंधित जानकारी पर विस्तृत प्रकाश डाला। इस मौके पर सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त कमलेश्वर नारायण, निदेशक डीआरडीबी राजीव रंजन, डीएलएओ राम नारायण खलको, एडीएम-सप्लाई मो जियाऊल अंसारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा, ट्रेजरी ऑफिसर पंकज कुमार, डीएसपी-सीसीआर सुमित कुमार व घनश्याम दुबे भी उपस्थित थे।

BRIEF NEWS

रांची विश्वविद्यालय में जल्द होगी एमएड की पढ़ाई : कुलपति

RANCHI : रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने शुक्रवार को एक बैठक में कहा कि जल्द ही शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एमएड की भी पढ़ाई होगी। कुलपति ने कांफ्रेंस हॉल शहीद चौक प्रशासनिक भवन में बीएड महाविद्यालयों के सभी प्राचार्यों के साथ एक अहम बैठक में यह निर्णय लिया। इस बैठक में प्राचार्यों ने अपने महाविद्यालयों की ओर से चलाए जा रहे संचालित आउटरीच कार्यक्रमों, अकादमिक पहलों और बीएड पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम (सिलेबस) के अद्यतन से संबंधित सुझाव भी साझा किए। इस दौरान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम में बदलाव पर विशेष चर्चा की गई।

ओबीसी को आरक्षण की मांग पर सुदेश को जेल भेजने की साजिश : आजसू

RANCHI : आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार ने पांच वर्ष पूर्व ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस, प्रवक्ता देवशरण भगत और पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता को जेल भेजने की साजिश कर रही है। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि कोर्ट में सभी नेताओं के खिलाफ आरोप गठित होना इसी दिशा में एक नया कदम है। प्रभाकर ने कहा है कि नगर निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिलवाने के लिए आजसू पार्टी सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, जिसके कारण झामुमोझकांग्रेस नाराज हैं। सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के सुप्रीम कोर्ट जाने पर नगर निकाय और पंचायत में ओबीसी आरक्षण देने पर राज्य सरकार विवश हुई है।

करदाताओं के लिए बनाई जा रहीं प्रक्रियाएं अधिक सरल : आयकर आयुक्त

RANCHI : मेंबर्स इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस कमिटी ऑफ दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली की ओर से इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन रांची के रैडिशन ब्लू होटल में शुक्रवार को किया गया। सेमिनार का उदघाटन मुख्य अतिथि राजेश झा, आईआरएस, मुख्य आयकर आयुक्त, रांची ने किया। मुख्य अतिथि राजेश झा, आईआरएस, मुख्य आयकर आयुक्त ने कर प्रणाली में पारदर्शिता और अनुपालन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि नए इनकम टैक्स एक्ट के माध्यम से करदाताओं के लिए प्रक्रियाएं अधिक सरल और प्रभावी बनाई जा रही हैं। उन्होंने उपस्थित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स से अपील की कि वे करदाताओं को सही मार्गदर्शन देकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें।

मनरेगा हड़ताल पर सख्ती, हड़तालियों की कड़ी निगरानी शुरू

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड में 12 मार्च से जारी मनरेगा कर्मियों की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए अब हड़ताली कर्मियों की निगरानी और पहचान तेज कर दी है। विभिन्न जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर हड़ताल में शामिल कर्मियों को कड़ी निगरानी सूची में रखा जा रहा है। विभागीय पोर्टल उन्हें अलग मार्किंग के साथ दर्ज करा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के सूत्रों के अनुसार, जो मनरेगा कर्मी हड़ताल पर हैं, उन्हें अलग सूची में डालकर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जो कर्मी काम पर लौट आए हैं या लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें इस सूची से बाहर रखा गया है, ताकि कार्यरत और हड़ताली कर्मियों के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके। राज्य के कई जिलों- चतरा, देवघर, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, सरायकेला-खरसावां और सिमडेगा से मिली जानकारी में सामने आया है कि अलग-अलग स्तर पर कर्मियों की स्थिति अपडेट की जा रही है। कई जिलों में अब भी बड़ी संख्या में कर्मी हड़ताल पर हैं, जबकि कुछ जगहों पर आंशिक रूप से काम शुरू हो चुका है।

- जो काम पर लौट आए हैं या पहले से कर रहे उन्हें निगरानी सूची से रखा गया है बाहर
- स्ट्राइक के कारण ऑनलाइन एंट्री, मस्टर रोल और भुगतान प्रक्रिया भी हो रही प्रभावित
- सिर्फ चार जिलों में ही अभियंता स्तर के कर्मी भी हड़ताल में हैं शामिल

हड़ताल पर जाने वालों की हो रही है पोर्टल पर मार्किंग

हड़ताल में शामिल मनरेगा कर्मी ● फोटोन न्यूज

जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर का समर्थन सीमित

आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में करीब 5 हजार मनरेगा कर्मी कार्यरत हैं, जिनमें से 2500 से अधिक ग्राम रोजगार सेवक हड़ताल पर हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सहायक और लेखा सहायक भी कई जिलों में हड़ताल में शामिल हैं, जिससे ऑनलाइन एंट्री, मस्टर रोल और भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर का का समर्थन सीमित दिख रहा है। सिर्फ चार जिलों में ही अभियंता स्तर के कर्मी हड़ताल में शामिल हैं, जबकि बाकी जिलों में इंजीनियर काम कर रहे हैं, जिससे तकनीकी कार्य पूरी तरह ठप नहीं हुआ है।

योजनाओं को पटरी पर लाने की कवायद

सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह कवायद मनरेगा योजनाओं को पटरी पर बनाए रखने और सक्रिय कर्मियों को प्राथमिकता देने के लिए की जा रही है। वहीं, हड़ताल में शामिल कर्मियों पर आगे प्रशासनिक कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है। दूसरी ओर मनरेगा कर्मियों के संगठन इसे दबाव की रणनीति बताते हुए विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि सेवा नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के कारण कई जिलों में मनरेगा का कामकाज प्रभावित हुआ है और योजनाओं की गति धीमी पड़ गई है।

आंशिक रूप से काम कर रहे कुछ कर्मी

रिपोर्ट के अनुसार, कई जिलों में 100 से 200 तक कर्मियों की स्थिति को लेकर डेटा अपडेट किया गया है। नॉर्मल और पार्शियली एक्टिव जैसी श्रेणियों में भी एंट्री की जा रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कुछ कर्मी आंशिक रूप से काम कर रहे हैं या हड़ताल से दूरी बना रहे हैं।

फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल्स सोसाइटी के तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में गवर्नर बोले-

युवा देश की असली ताकत, विकसित राष्ट्र निर्माण में निभाएं अहम भूमिका

PHOTON NEWS RANCHI : शुक्रवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि देश का वर्तमान और भविष्य युवाओं के हाथों में है और उनकी ऊर्जा ही भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। वे रांची में फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल्स सोसाइटी की ओर से आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन -अभिज्ञ 3.0 को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल्स सोसाइटी की यात्रा सेवा, समर्पण और सामाजिक बदलाव का प्रेरक उदाहरण रही है। यह संगठन जनजातीय समाज के उत्थान के लिए एक बड़े जन-आंदोलन के रूप में कार्य कर रहा है, जिसने शिक्षा, संस्कृति और आत्मगौरव के जरिए लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। उन्होंने एकल शिक्षा की अवधारणा की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा और जागरूकता पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही है।

सोसाइटी की यात्रा सेवा, समर्पण और सामाजिक बदलाव का प्रेरक उदाहरण

कार्यक्रम को संबोधित करते राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ● फोटोन न्यूज

आत्मनिर्भरता को दिया जा रहा बढ़ावा

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत जनजातीय समाज के उत्थान, शिक्षा विस्तार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत को सशक्त बनाने का रास्ता केवल नीतियों से नहीं, बल्कि हमारी सोच, आचरण और संस्कारों से तय होगा।

समाज के अंतिम व्यक्ति तक जागरूकता फैलाने में एकल शिक्षा की अवधारणा महत्वपूर्ण

अपनी संस्कृति और मूल्यों पर करें गर्व

राज्यपाल ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि भारतवासी होने का मतलब अपनी संस्कृति और मूल्यों पर गर्व करना है, साथ ही समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि युवाओं की सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प ही देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें समावेशी और संतुलित विकास की परिकल्पना की गई है। इस लक्ष्य को हासिल करने में जनजातीय समाज की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। गांवों और वनवासी क्षेत्रों के सशक्त होने से ही भारत का समग्र विकास संभव है।

कुपोषण से लड़ने में आसानी से उपलब्ध स्थानीय साग-सब्जियों की भूमिका अहम

- 'वाइल्ड लीफ वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स' पुस्तक के लोकार्पण समारोह में राज्यपाल ने कहा-
- पोषण से भरपूर होने के साथ-साथ औषधीय गुणों से समृद्ध होते हैं प्राकृतिक खाद्य पदार्थ
- नियमित रूप से दैनिक आहार में शामिल कर बड़े स्तर पर किया जा सकता है स्वास्थ्य सुधार

RANCHI : शुक्रवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि झारखंड के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में उपलब्ध पारंपरिक साग-सब्जियां और फूल न केवल भोजन का हिस्सा हैं, बल्कि कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से निपटने का सशक्त माध्यम भी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध ये प्राकृतिक खाद्य पदार्थ पोषण से भरपूर होने के साथ-साथ औषधीय गुणों से समृद्ध हैं। इन्हें दैनिक आहार में शामिल कर बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सुधार किया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि बदलती जीवनशैली में पारंपरिक खाद्य आदतों का महत्व और बढ़ गया है, ऐसे में इन साग-सब्जियों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। राज्यपाल ने यह बातें लोकभवन में रांची विश्वविद्यालय की प्रो.वंदना कुमारी और प्रो. सुधांशु कुमार (सेवानिवृत्त) द्वारा लिखित पुस्तक 'वाइल्ड लीफ वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स' पुस्तक के लोकार्पण समारोह में अपने संबोधन में कही। गवर्नर ने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि इसमें 250 से अधिक प्रकार के पत्तों और फूलों का वैज्ञानिक विवरण छायाचित्रों के साथ दिया गया है, जो खासकर जनजातीय क्षेत्रों की पारंपरिक खाद्य संस्कृति को सामने लाता है।

30 साल सेवा पर 104 सचिवालय कर्मियों को तीसरा वेतन उन्नयन

RANCHI : राज्य सरकार ने सचिवालय सेवा के 104 अधिकारियों और कर्मचारियों को तीसरा संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने आदेश जारी किया है। यह लाभ 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर दिया गया है। विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित कर्मियों को उनके नाम के समक्ष निर्धारित तिथि से वेतन स्तर-12 में वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दी गई है। अधिकतर मामलों में यह लाभ दिसंबर 2025 से प्रभावी माना गया है। सूची में अवर सचिव स्तर के कई अधिकारी शामिल हैं, जो कृषि, वन एवं पर्यावरण, राजस्व परिषद, गृह, ग्रामीण विकास और वित्त विभाग में कार्यरत हैं। स्पष्ट किया गया है कि यह उन्नयन व्यक्तिगत आधार पर दिया गया वित्तीय लाभ होगा और इसका वरिष्ठता क्रम से कोई संबंध नहीं रहेगा। साथ ही लाभार्थियों से यह भी सुनिश्चित कराया जाएगा कि किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जा सके।

मंत्री इरफान अंसारी ने यूट्यूब चैनल को भेजा 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस

PHOTON NEWS RANCHI : स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री इरफान अंसारी ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने, दुर्भावनापूर्ण मीडिया ट्रायल चलाने और सांप्रदायिक संकेतों के जरिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में रांची के एक स्थानीय यूट्यूब चैनल के खिलाफ कड़ा कानूनी कदम उठाया है। मंत्री की ओर से 23 अप्रैल 2026 को अधिवक्ताओं के माध्यम से 10 करोड़ रुपए का फाइनल एवं बाईडिंग लीगल नोटिस जारी किया गया।

मंत्री ने शुक्रवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि नोटिस में संबंधित मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित और प्रसारित सामग्री को पूर्व-नियोजित, दुर्भावनापूर्ण और चरित्र-हनन करने वाला है। जिसमें एकतरफा

मंत्री इरफान अंसारी

मीडिया ट्रायल के जरिए जनमानस में भ्रामक और गलत धारणा बनाने का प्रयास किया गया, जो पत्रकारिता की मर्यादाओं का उल्लंघन है। साथ ही मंत्री ने उसमें प्रयुक्त भाषा को सांप्रदायिक संकेतों से युक्त बताते हुए इसे सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने वाला करार दिया है।

नोटिस में मंत्री ने चैनल के समक्ष तीन प्रमुख मांगें रखी हैं जिनमें संबंधित यूट्यूब चैनल के सभी प्लेटफॉर्म से विवादित कंटेंट को तत्काल हटाने, डॉ. अंसारी से सार्वजनिक और बिना शर्त माफी मांगे जाने तथा ऐसा नहीं करने पर 10 करोड़ का हर्जाना अदा करने की मांगे शामिल है। नोटिस के माध्यम से चैनल को निर्धारित समय-सीमा में मांगें पूरी नहीं होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

मंत्री ने कहा कि इस कंटेंट से उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची है और उन्हें मानसिक पीड़ा व सार्वजनिक अपमान झेलना पड़ा, जो अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्मान की बात करते हुए स्पष्ट किया कि झूठ और समाज को बांटने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गार्ड हत्या के विरोध में आदिवासी संगठनों ने किया प्रदर्शन

RANCHI : राजधानी रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में तैनात गार्ड बिरसा मुंडा की हत्या के विरोध में आदिवासी संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर और बांस लगाकर सड़क जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। बाद में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) पीके मिश्रा सहित पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और जाम हटवाया।

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि शहर में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब वे धार्मिक स्थलों तक को निशाना बनाने लगे हैं।

जगन्नाथपुर मंदिर प्रहरी हत्याकांड पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार और पुलिस पर उठाए सवाल

PHOTON NEWS RANCHI : राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के गर्भगृह की सुरक्षा में तैनात प्रहरी की हत्या के बाद राज्य की सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस घटना की सूचना से वे स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में यह वारदात हुई है, वहां विधानसभा और उच्च न्यायालय जैसे अत्यंत संवेदनशील संस्थान स्थित हैं। ऐसे हाई सिक्योरिटी जोन में मंदिर परिसर के भीतर घुसकर हत्या हो जाना पुलिस की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। उन्होंने कहा कि पिछले

भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ● फोटोन न्यूज

दो दिनों के भीतर मंदिर के आसपास दो हत्याएं हो चुकी हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि रांची पुलिस अपराध रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। मरांडी ने पुलिस की कार्यप्रणाली की तुलना 'सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटने' वाली स्थिति से करते हुए कहा कि पुलिस केवल घटना के बाद सक्रिय होती है, जबकि अपराध रोकने की जिम्मेदारी पहले की होती है। भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले पर चुप्पी तोड़ने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की खामोशी अपराधियों और अयोग्य पुलिस अधिकारियों का मनोबल बढ़ा रही है। यदि सरकार समय रहते सख्त कदम नहीं उठाती है, तो कानून-व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ सकती है।

नियमों में बदलाव | 120 दिनों में फैसला नहीं तो आवेदन खारिज

खनन पट्टा की स्वीकृति के पहले ग्रामसभा की अनुमति अनिवार्य

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड सरकार ने खनन व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली- 2026 लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत खनन पट्टा से जुड़ी प्रक्रिया को समयबद्ध और सख्त बनाया गया है। अब पट्टा के लिए प्राप्त आवेदनों पर 120 दिनों के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन स्वतः खारिज माना जाएगा। उपायुक्त द्वारा इस आशय का पत्र जारी किया जाएगा। इस पत्र की वैधता निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी मान्य होगा। खनन पट्टा के प्रत्येक आवेदन पर निर्णय उपायुक्त द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रदत्त पर्यावरणीय सुरक्षा प्रमाण पत्र दाखिल करने के 30 दोनों को भीतर दिया जाएगा 30 दोनों को अवधि के पश्चात आवेदन खान निदेशालय को भेजा जाएगा जिसका 30 दिनों के भीतर निर्देशक खान द्वारा निर्णय लिया जाएगा। दाखिल आवेदन पत्र पर 120 दिनों के अंदर आशय पत्र जारी किया जाएगा। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में खनन पट्टा की स्वीकृति के पूर्व ग्राम सभा का स्वतंत्र एवं पूर्व सहमति प्राप्त किया जाना अब अनिवार्य किया गया। नियमावली के अनुसार 3 हेक्टेयर तक की रैयती भूमि पर पत्थर, मोरम और मिट्टी के पट्टे आवेदन के आधार पर दिए जाएंगे, जबकि इससे अधिक क्षेत्र और अन्य खनिजों के लिए पट्टे ई-नीलामी के माध्यम से दिए जाएंगे। आवेदन के लिए 25 हजार रुपये शुल्क, आयकर विवरणी और स्वामित्व या सहमति पत्र अनिवार्य किया गया है। संशोधन के बाद कई मामलों में राज्य सरकार की जगह निदेशक, खान को निर्णय का अधिकार दिया गया है। सक्षम पदाधिकारी की परिभाषा का विस्तार करते हुए उपायुक्त से लेकर जिला खनन पदाधिकारी तक को इसमें शामिल किया गया है।

लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली- 2026 लागू

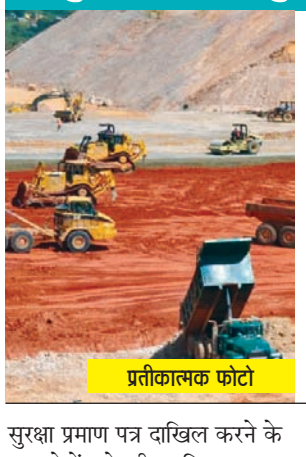

प्रतीकात्मक फोटो

सख्त कार्रवाई का किया गया प्रावधान

अवैध खनन, भंडारण और परिवहन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। नियम उल्लंघन को दंडनीय अपराध माना जाएगा। किसी आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति 30 दिनों के भीतर 1000 रुपये शुल्क के साथ ऑनलाइन अपील कर सकेगा। अन्य प्रावधानों के तहत लगान या स्वामित्व भुगतान नहीं करने अथवा शर्तों के उल्लंघन पर पट्टा समाप्त किया जा सकेगा। पट्टा समाप्ति के बाद 60 दिनों के भीतर खनिज हटाना अनिवार्य होगा। पट्टा की प्रभावी तिथि निबंधन की तिथि मानी जाएगी। लघु खनिज पट्टाधारियों को जिला खनिज प्रतिष्ठान के तहत देय राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा कुछ मामलों में शुल्क 1000 रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है और मान्यता प्राप्त आवेदकों का निबंधन अधिकतम तीन वर्ष के लिए मान्य होगा। बालू खनन अब राज्य के निर्धारित सैंड माइनिंग नियम, 2025 के अनुसार किया जाएगा। सरकार का मानना है कि नई नियमावली से खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, अवैध खनन पर रोक लगेगी और राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।

जुडको में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन

RANCHI : जुडको के प्रशासनिक शाखा द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हेल्थ कैंप का आयोजन शुक्रवार को किया गया। हेल्थ कैंप में 50 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की विभिन्न चिकित्सकीय जांच की गयी और अनुभवी डाक्टरों द्वारा उपचार से संबंधित उचित सलाह भी दी गयी। सेंटर फार साइट आइ हास्पीटल के चिकित्सकों द्वारा मोतियाबिंद और आंख से संबंधित अन्य बीमारियों की जांच की गयी। इसके अलावा निषुल्क नेत्र परीक्षण भी किया गया। रेटिना की भी जांच की गयी। सेंटर फार साइट के प्रबंधक एम सोहन राव, सीनियर आप्टेमेटिस्ट साहिल और पीसीटी दीलीप राम ने नेत्र परीक्षण में मुख्य भूमिका निभाई।

जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति का पुनर्गठन, नई कमेटी गठित

PHOTON NEWS RANCHI : जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति का पुनर्गठन कर नई कमिटी का गठन किया गया है। पूर्व में गठित समिति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह निर्णय लिया गया।

नई समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एन.एन. पाण्डेय को अध्यक्ष बनाया गया है। ठाकुर सुधांशु नाथ शाहदेव (प्रथम सेवक, सेवायत) को उपाध्यक्ष, मिथिलेश कुमार को उपाध्यक्ष तथा प्रसन्न कुमार को सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा विनोद कुमार, लाल प्रेम प्रकाश नाथ शाहदेव, मुकेश कुमार, कमल ठाकुर, भरत तिवारी, नीतू देवी और गोपाल उपाध्याय को सदस्य बनाया गया है।

समिति में सांसद रांची, विधायक खिजरी, विधायक हटिया, उपायुक्त रांची एवं सदर अनुमंडल पदाधिकारी रांची को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। न्यास समिति को मंदिर की संपत्तियों के संरक्षण, आय-व्यय के पारदर्शी प्रबंधन, दान व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा मंदिर के समग्र विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही, समिति मंदिर में पूजा-अर्चना एवं रथ यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेगी। नई समिति को तीन महीने के भीतर मंदिर के कुशल प्रबंधन और समग्र विकास के लिए विस्तृत योजना तैयार करने का दायित्व दिया गया है।

समाचार सार

एडवोकेट अनिल कुमार महतो लगातार तीसरी बार जीते

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिला बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार महतो के झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में तीसरी बार भारी मतों से विजयी हुए। इस खुशी में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को बार परिसर में जमकर आतिशबाजी की और अनिल कुमार महतो को फूलमाला से अभिनंदन किया। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के महासचिव फादर अगस्तिन कुल्लू, निरंजन प्रसाद साव, अंकुर कुमार चौधरी, सतीश चंद्र महतो, नीरज कुमार, रमेश चौबे, सुभाष चंद्र मिश्रा, किशोर महतो, कैसर परवेज, राजाराम गुप्ता सहित कई अधिवक्ता उपस्थित थे।

टेल्को में महिला से चेन छिनतई

JAMSHEDPUR : टेल्को कॉलोनी स्थित मिलेनियम पार्क के पास बाइक सवार दो बदमाश एक महिला के गले से चेन छीन कर फरार हो गए। जिस महिला के गले से चेन छीनी गई है, वह टेल्को कॉलोनी में के 3/39 की निवासी है। वह अपने पति प्रताप कुमार प्रतापी के साथ मिलेनियम पार्क गई थी। यह घटवा पार्क से घर लौटते समय हुई। शुक्रवार को पुलिस मामले की एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। टेल्को थाना प्रभारी ने बताया कि घटना गुरुवार शाम 5.40 बजे की है।

एसडीओ श्रुति राजलक्ष्मी सहित 40 ने किया रक्तदान

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिला में रक्त की कमी को देखते हुए उपायुक्त के निर्देश पर शुक्रवार को चक्रधरपुर स्थित अनुमंडल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घतन पोड़ाहाट की अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी ने दीप जलाकर किया। इसके पश्चात उन्होंने भी रक्तदान किया। शिविर में कुल 40 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। एसडीओ ने बताया कि प्रत्येक माह की 24 तारीख को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरूआत आज से की गई। शिविर को सफल बनाने में प्रखंड विकास पदाधिकारी कांचन मुखर्जी, अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अंशुमन शर्मा, जेएलएन कॉलेज के कर्मचारी, सीआरपीएफ 60 बटालियन के जवानों के अलावा शहर के गणमान्य लोगों ने भी रक्तदान किया।

अनुकंपा पर तीन को मिली नियुक्ति

JAMSHEDPUR : समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त राजीव रंजन ने अनुकंपा नियुक्ति के तहत तीन कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। अनुकंपा के आधार पर अमित बेरा एवं सुभाष हांसदा को वर्ग-3 (निम्नवर्गीय लिपिक) पद तथा जयंत सिंह को वर्ग-4 (अनुसेवी) पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। उपायुक्त ने नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की बात कही। उन्होंने कर्मियों से अपेक्षा की कि वे कार्यालयी कार्यों में पारदर्शिता, अनुशासन एवं जवाबदेही का पालन करते हुए जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

खरसावां में 4 शराब भट्ठी ध्वस्त, 1200 किलो महुआ बरामद

SERAIKELA : सरायकेला-खरसावां जिले के उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह के निर्देश पर उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में खरसावां थाना अंतर्गत ग्राम पुनीदा एवं गांगुडीह में छापे कर चार अवैध चुलाई शराब अड्डों को ध्वस्त किया गया तथा लगभग 1200 किलोग्राम जावा महुआ बरामद किया गया। बरामद महुआ को जब्त करते हुए संबंधित अड्डा संचालकों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया।

पटमदा में बच्चों ने मनाया सचिन का जन्मदिन

JAMSHEDPUR : पटमदा में शुक्रवार को बच्चों ने क्रिकेट लिजेंड सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर एसएस +2 उच्च विद्यालय, पटमदा मैदान पर सचिन एकादश एवं मिताली राज एकादश के बीच मिक्स जेंडर मुकाबला खेला गया। सचिन एकादश की कप्तान पूजा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सचिन एकादश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 5 ओवर्स में एक विकेट के नुकसान पर कुल 53 रन बनाए। 54 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मिताली राज एकादश की शुरूआत बेहद धीमी रही, मिताली एकादश 5 ओवर्स की समाप्ति पर एक विकेट खोकर कुल 27 रन ही बना सकी।

एमजीएम अस्पताल के बंदी वार्ड से कूद कर विचाराधीन कैदी ने की आत्महत्या

डॉक्टर के पास जांच के लिए ले जाते समय सिपाही से हाथ छुड़ाकर सातवीं मंजिल से लगाई छलांग

PHOTON NEWS JSR : मानगो स्थित एमजीएम अस्पताल में शुक्रवार को इलाजरत विचाराधीन कैदी ने सात मंजिला भवन से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम अशोक कुमार है। गौरतलब है कि अशोक कुमार पहले से ही मानसिक तनाव से गुजर रहा था। बताया जाता है कि उसने जेल के अंदर भी खुद का गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन समय रहते जेल प्रशासन ने उसे बचा लिया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया था। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शुक्रवार को दोपहर में उसे कैदी वार्ड से डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने पुलिसकर्मी का हाथ छुड़ा लिया और अचानक सातवीं

मंजिल से कूद गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद एक बार फिर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जाता है कि अशोक कुमार लंबे समय से जेल में बंद था और मानसिक रूप से अस्वस्थ था। उसके बेहतर इलाज के लिए उसे रांची भी भेजा गया था, जहां उसका इलाज चल रहा था।

गौरतलब है कि एमजीएम अस्पताल में ऊपर की मंजिलों में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो खुले हुए हैं। यहां से कूद कर आत्महत्या की जा सकती है। वार्ड की खिड़कियों में स्लाइडर लगा है, लेकिन जालियां नहीं लगीं। पहले भी मरीज यहां से कूद कर आत्महत्या कर चुके हैं।

सरायकेला में होमगार्ड बहाली में बड़ा घोटाला : एक ही पते पर 73 आवेदक, कड़ी कार्रवाई की मांग

आदित्यपुर में पत्रकारों को संबोधित करते होमगार्ड एसोसिएशन के पदाधिकारी

SERAIKELA : सरायकेला-खरसावां जिले में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया में एक बड़े घोटाले की बात सामने आ रही है। आदित्यपुर स्थित आदिवासी कल्याण समिति में शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव तिवारी ने बताया कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर बाहरी राज्यों के लोगों को स्थानीय बताकर नौकरी दी गई है। राजीव तिवारी ने दस्तावेजों के हवाले से बताया कि बहाली में नियमों को ताक पर रखकर फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बांटे गए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिले में एक ऐसा पता सामने आया है, जहां से 73 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और उनमें से 24 सफल भी हो गए। इसी प्रकार, एक अन्य पते पर 11 में से 8 और अन्य स्थानों पर शत-प्रतिशत संदिग्ध चयनित हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि एक ही पते पर इतने लोग कैसे रह सकते हैं और प्रशासन ने बिना भौतिक सत्यापन के इन्हें प्रमाण पत्र कैसे जारी कर दिए। महासचिव ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यह न केवल स्थानीय युवाओं के रोजगार का हनन है, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गंभीर मामला है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि यही प्रक्रिया रही, तो भविष्य में कोई भी विदेशी नागरिक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सुरक्षातंत्र में घुसपैठ कर सकता है।

टाटा स्टील प्लांट में चोरी की कोशिश नाकाम, तीन आरोपी हुए गिरफ्तार

PHOTON NEWS JSR : टाटा स्टील प्लांट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की मुस्तैदी एक बार फिर देखने को मिली, जब कंपनी की सुरक्षा टीम ने बड़ी चोरी की कोशिश को विफल करते हुए तीनआरोपितों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह घटना 24 अप्रैल 2026 की तड़के करीब एक बजे की बताई जा रही है, जब संदिग्ध गतिविधि पर नजर पड़ते ही सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, तीनों आरोपी सकची क्षेत्र स्थित केबल गैलरी के रास्ते प्लांट परिसर में अवैध रूप से प्रवेश कर चुके थे और तांबे के केबल को काटकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान गश्त कर रही सुरक्षा टीम की नजर उन पर पड़

पुलिस गिरफ्त में आरोपी

गई। सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए पूरे इलाके को घेर लिया और थोड़ी मशक्कत के बाद तीनों को मौके पर ही पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपितों के पास से लगभग 75 किलो तांबे का केबल बरामद किया गया, जिसकी बाजार में अच्छी कीमत बताई जा रही है। अगर यह चोरी सफल हो जाती तो कंपनी को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता था। सुरक्षा टीम की सतर्कता के कारण इस नुकसान को समय रहते टाल दिया गया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान विकाश चिन्ना (ओल्ड सीतारामडेरा थाना क्षेत्र), दीपक लोहार (बिरसानगर रोड नंबर 7) और अविनाश मुखी (केबल टाउन बस्ती रोड नंबर 5) के रूप में हुई है। तीनों स्थानीय क्षेत्र के रहने वाले हैं और प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि वे पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल हो सकते हैं। घटना के बाद टाटा स्टील के सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी आरोपियों को बिष्टुपुर थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इस घटना के पीछे कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है।

आवास योजना में लापरवाही बरतने पर दो प्रखंड समन्वयकों की सेवा समाप्त

JAMSHEDPUR : पूर्वी सिंहभूम जिला में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला चयन समिति द्वारा कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान आवास योजना के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्य निष्पादन, प्रगति प्रतिवेदन एवं क्षेत्रीय कार्यों के आधार पर प्रखंड समन्वयकों के कार्यों का मूल्यांकन किया गया। जिला चयन समिति द्वारा की गई समीक्षा में प्रखंड समन्वयक, डुमरिया साजल कुमार खान तथा प्रखंड समन्वयक, गुड़ाबांदा धर्मेंद्र प्रसाद का कार्य निष्पादन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत असंतोषजनक एवं अपेक्षित स्तर से कम पाया गया। उक्त परिस्थितियों को देखते हुए जिला चयन समिति की अनुशंसा पर दोनों प्रखंड समन्वयकों की संविदा सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

गोइलकेरा में साल की लकड़ी लदा ट्रक जब्त, चालक गिरफ्तार

ट्रक पर लदी लकड़ी

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार की रात संतरा वन प्रक्षेत्र की टीम ने भारी मात्रा में साल की लकड़ी से लदा एक ट्रक पकड़ा है। ट्रक के साथ बिहार निवासी चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार, वन विभाग के रेंजर रामनंदन राम को गुप्त सूचना मिली थी कि गोइलकेरा और चाईबासा के बीच जंगल से लकड़ी काटकर ट्रक में लोड कर बिहार भेजा जा रहा है। सूचना के आधार पर संतरा वन प्रक्षेत्र के कर्मियों ने रात करीब एक बजे गोइलकेरा के गोटांबा गांव के पास घेराबंदी कर ट्रक को रोका गया। जब्त ट्रक पर साल के 44 बोटे लदे थे। बरामद लकड़ी की अनुमानित बाजार कीमत पांच लाख रुपये आंकी गई है। पकड़ा गया ट्रक चालक बिहार के शाहगंज गांव के पोस्ट ईटवा जिला फतेहपुर निवासी कैलाश यादव है। पूछताछ में सामने आया कि कैलाश यादव ही जब्त ट्रक का मालिक भी है। विभाग यह भी जांच कर रहा है कि इस तस्करी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, गुरुवार की रात पकड़े गए ट्रक को समीज आश्रम के पास लोड किया गया था।

नौकरी छीनकर केंद्र व राज्य सरकार बना रही बेरोजगार : एसयूसीआई

आमसभा को संबोधित करते सोमेन बोस

GHATSILA : सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) झारखंड राज्य कमेटी की ओर से पार्टी के 79वें स्थापना दिवस पर शुक्रवार को शिवदास घोष अध्ययन केंद्र काशीदा में विशाल आमसभा हुई। इस मौके पर झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुख्य वक्ता पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य सोमेन बोस ने कहा कि आज एक तरफ सभी बड़ी-बड़ी पूंजीपति वर्ग की पार्टी टूट रही है, वहीं दूसरी ओर इस देश की एकमात्र सही वामपंथी पार्टी एसयूसीआई-सी पूरे देश में ताकत के साथ आम जनता का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ रही है। आज चाहे वह केंद्र की बड़ी पार्टी हो या राज्य की क्षेत्रीय पार्टियां, जो बारी-बारी से सरकार में रही हैं-आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय जन विरोधी, शिक्षा विरोधी, किसान विरोधी ,मजदूर विरोधी कानून को लागू कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है, नौकरी देने के बजाय सरकार सरकारी एवं प्राइवेट दोनों नौकरियां आम लोगों से छीन रही है। बगल की टाटा कंपनी के अंदर टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के कर्मचारियों को जबरन वीआरएस देकर निकालने की साजिश चल रही है।

पश्चिमी सिंहभूम के 6 प्रखंडों में 252 यूनिट रक्त हुआ संग्रह

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रोजेक्ट जागृति की शुरूआत शुक्रवार को हुई। इसके तहत जिले के 6 प्रखंडों में 252 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शुक्रवार को जिले मे आयोजित रक्तदान शिविर के आलोक में प्रखंड सदर चाईबासा के एमटीसी सदर अस्पताल कैंपस में कुल 105 डोनर ने पंजीकृत किया और 99 यूनिट, तांतनगर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 37 डोनर ने पंजीकृत किया और 36 यूनिट, प्रखंड झींकपानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 40 डोनर ने पंजीकृत किया और 33 यूनिट, टोन्टो प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मे 36 डोनर ने पंजीकृत किया और 22 यूनिट, प्रखंड मंझारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मे 39 डोनर ने पंजीकृत किया और 22 यूनिट, प्रखंड चक्रधरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मे 53 डोनर ने पंजीकृत किया और 40 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। रक्तदान शिविर में जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, कर्मचारियों, सामाजिक संगठन और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वैच्छिक रूप से रक्तदान किया साथ ही दूसरों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया।

तस्करों से बचाई गई 6 नाबालिग बच्चियां चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर हुई कार्रवाई

- रांची की संस्था से मिली थी सूचना, आरपीएफ और जीआरपी ने मिलकर बच्चियों को बचाया

CHAKRADHARPUR : झारखंड सहित पश्चिमी सिंहभूम जिला से मानव तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, हर हफ्ते जिले से सैकड़ों नाबालिग महिला-पुरुष मानव तस्करों के चक्कर में आकर पलायन कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण है, गुरुवार की रात चक्रधरपुर स्टेशन में देखने को मिला। जहां नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर चलाए गए एक संयुक्त अभियान में 6 बच्चियों को तस्करी की आशंका से सुरक्षित बचा लिया गया। रांची की एक सामाजिक संस्था के सहयोग से विभिन्न विभागों की टीम ने समय रहते कार्रवाई कर बड़ी अनहोनी टाल दी। जानकारी के अनुसार, रेस्क्यू की गई सभी बच्चियों की उम्र लगभग 14 से 16 वर्ष के बीच है। अधिकारियों ने बताया कि इन बच्चियों को बहला-फुसलाकर और पैसे के सपने दिखाकर दूसरे राज्यों की ओर ले जाया जा रहा था। गुप्त सूचना और सतर्कता के चलते संयुक्त टीम ने इन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इस रेस्क्यू अभियान में चक्रधरपुर के थाना प्रभारी अवधेश कुमार के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी, रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन, श्रम विभाग, चक्रधरपुर महिला थाना और जिला विधिक सेवा प्राधिकार, चाईबासा की अहम भूमिका रही। रांची स्थित एक सामाजिक संस्था ने भी टीम को सहयोग किया। थाना प्रभारी अवधेश कुमार ने बताया कि त्वरित कार्रवाई और आपसी समन्वय के कारण एक गंभीर स्थिति को टाल दिया गया। फिलहाल सभी बच्चियों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। बाल कल्याण समिति के निर्देश पर कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके साथ ही बच्चियों की काउंसलिंग भी कराई जा रही है, ताकि ये नाबालिग बच्ची पढ़ाई-लिखाई कर बेहतर जिंदगी जी सकें। अधिकारियों का कहना है कि नाबालिगों की सुरक्षा के लिए जिले में लगातार निगरानी और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि बच्चों से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या संबंधित विभाग को दें। समय पर सूचना मिलने से कई मासूमों को तस्करी और शोषण से बचाया जा सकता है।

सेमिनार सतत गुणवत्तापूर्ण इस्पात निर्माण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य समापन, वैश्विक विशेषज्ञों ने साझा किए विचार

इस्पात निर्माण में इलेक्ट्रिक आर्क व इंडक्शन फर्नेस का भविष्य : राजीव मंगल

PHOTON NEWS JSR : बिष्टुपुर के एन रोड स्थित शावक नानावती तकनीकी संस्थान (एसएनटीआई) में सतत गुणवत्ता इस्पात निर्माण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीएसक्यूएस-2026) का समापन शुक्रवार को हो गया। दो दिवसीय सम्मेलन में देश-विदेश के ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञों, इस्पात उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों, तकनीकी वैज्ञानिकों तथा शोधकताओं ने भाग लिया और इस्पात निर्माण के भविष्य पर गहन विचार-विमर्श किया।

समापन समारोह को टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सततता) राजीव मंगल ने संबोधित किया। उन्होंने विशेष रूप से स्क्रैप आधारित मार्ग से इस्पात उत्पादन में सुरक्षा मानकों को मजबूत करने तथा गुणवत्ता आश्वासन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) और इंडक्शन फर्नेस (आईएफ) आधारित इस्पात निर्माण प्रणाली तेजी से विकसित हो रही है, ऐसे में उत्पादन प्रक्रिया में सुरक्षा, स्थिरता और गुणवत्ता नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।

राजीव मंगल ने अपने संबोधन में टाटा स्टील द्वारा विद्युत आर्क भट्ठी आधारित उत्पादन प्रणाली की दिशा में हो रही प्रगति पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यूरोप में इस्पात की मांग अपेक्षाकृत स्थिर होने के कारण वहां ईएएफ आधारित उत्पादन प्रणाली की ओर धीरे-धीरे बदलाव देखा जा रहा है, जबकि भारत में इस्पात की मांग तीव्र गति से बढ़ रही है। साथ ही,

कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथि ● फोटोन न्यूज

कार्बन उत्सर्जन कम करने पर ज्यादा जोर

दो दिवसीय इस सम्मेलन का समापन एक फीडबैक सत्र के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने आयोजन को अत्यंत सफल, ज्ञानवर्धक और उद्योग के भविष्य के लिए उपयोगी बताया। पहले दिन उद्घाटन सत्र के साथ विभिन्न तकनीकी सत्र, मुख्य व्याख्यान और पैनल चर्चाओं का आयोजन किया गया, जिनमें सतत विकास की चुनौतियों, स्क्रैप की गुणवत्ता सुधार, इस्पात की शुद्धता, ऊर्जा दक्षता तथा विद्युत आर्क भट्ठी और इंडक्शन भट्ठी आधारित उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई।

पर्यावरणीय मानकों को भी लगातार अधिक कठोर बनाया जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक है कि ब्लास्ट फर्नेस और ईएएफ दोनों उत्पादन मार्गों का संतुलित विकास किया जाए, ताकि देश की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ-साथ सतत विकास के लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि इस्पात उद्योग को प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सुरक्षा, गुणवत्ता, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिल सके। इससे भारतीय इस्पात उद्योग वैश्विक स्तर पर और अधिक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बन सकता है। दूसरे दिन तकनीकी सत्रों में भट्ठी या फर्नेस तकनीक के आधुनिक विकास, कच्चे माल के बेहतर उपयोग, धातुकर्मीय प्रक्रिया नियंत्रण, डिजिटल तकनीक के उपयोग तथा उत्पादन प्रक्रिया के अनुकूलन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। विशेषज्ञों ने इस्पात निर्माण में नवाचार और स्वचालन की भूमिका को भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया।

इनकी भी रही उपस्थिति : कार्यक्रम के दौरान मंच पर टाटा स्टील के लॉन्ग प्रोडक्ट्स गुणवत्ता नियंत्रण प्रमुख डॉ. टी. भास्कर, जेमिपोल के मुख्य तकनीकी अधिकारी डॉ. एस. सान्याल तथा आईसीएसक्यूएस-2026 के सह-सचिव डॉ. ए. अम्मासी भी उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने इस्पात उद्योग में तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और उत्पादन दक्षता को बढ़ाने पर अपने विचार साझा किए।

जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 11 मई से समर कैंप का आयोजन

पत्रकारों को संबोधित करते टाटा स्टील के वीपी डीबी सुंदरा रामम

JAMSHEDPUR : टाटा स्टील के स्पोर्ट्स डिवीजन ने शुक्रवार को बहुप्रतीक्षित समर कैंप 2026 के आयोजन की घोषणा की। यह कैंप 11 मई से 31 मई तक जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। खेलों के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव के अपने लंबे समय से जारी प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को सीखने, निखरने और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए एक सशक्त और जीवंत मंच प्रदान करना है।

जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में टाटा स्टील के वीपी-कॉरपोरेट सर्विसेज डीबी सुंदरा रामम ने बताया कि पिछले वर्ष के समर कैंप की शानदार सफलता को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें जमशेदपुर में 2,995 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, टाटा स्टील को इस वर्ष 3,500 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में समावेशिता पर भी विशेष जोर दिया जाएगा, जिसके तहत 40 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और लगभग 60 बच्चे ह्यमस्ती की पाठशालाह्न से भी इस कैंप में भाग लेंगे।

BRIEF NEWS

विषाक्त मिठाई खाने से दर्जनों बच्चे बीमार

NAWADA : नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के मनहर गांव में शादी की खुशियां उस समय चिंता में बदल गईं, जब शुक्रवार को विषाक्त मिठाई खाने के बाद दर्जनों बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और परिजनों की आंखों में चिंता साफ झलकने लगी। जानकारी के अनुसार, गांव निवासी ओंकार सिंह के बेटे की शादी 20 तारीख को संपन्न हुई थी। शादी के बाद बची हुई मिठाई 24 तारीख को गांव के बच्चों और ग्रामीणों में बांटी गई। मिठाई खाने के कुछ ही देर बाद कई बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और ब्लोटिंग की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते बच्चों की हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों में हड़कंप मच गया। बीमार होने वालों में नीरज कुमार, पलक कुमारी, शीला देवी, अमृता कुमारी, आरोही कुमारी, रिमझिम कुमारी, आयुष कुमार, अंशिका कुमारी और ऋषिका कुमारी समेत कई बच्चे शामिल हैं। परिजन आनन-फानन में सभी बच्चों को रजौली अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। अस्पताल में तैनात डॉक्टर सूरज कुमार ने सभी बच्चों का प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टर के अनुसार, फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं और उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। घटना के बाद गांव में दहशत और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि संभवतः बासी मिठाई खाने के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ी। फिलहाल सभी बच्चों का इलाज जारी है और परिजन उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं।

पजिअरवा कांड के मुख्य आरोपी गिरफ्तार

EAST CHAMPARAN : जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के बहुचर्चित पजिअरवा कांड (संख्या 175/26) में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले के मुख्य आरोपी शेख साहिल को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही, जिस युवती के मामले को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ था, उसे भी आरोपी के साथ बरामद कर लिया गया है। यह मामला कथित रूप से 'लव जिहाद' से जुड़ा होने के कारण पिछले कई दिनों से जिले में चर्चा का केंद्र बना हुआ था। विश्व हिन्दू परिषद सहित कई संगठनों द्वारा लगातार धरना-प्रदर्शन कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी थी। इससे पहले इसी कांड में नामजद एक अन्य आरोपी साहेब मियां को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी और अंततः छत्तीसगढ़ में उसे पकड़ने में सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में छत्तीसगढ़ पुलिस का सहयोग लिया गया। संयुक्त अभियान के तहत आरोपी और युवती को बरामद किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सुगौली पुलिस टीम जल्द ही छत्तीसगढ़ रवाना होगी और आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मोतिहारी लाया जाएगा। वहीं युवती को भी सुरक्षित लाकर नियमानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पूछताछ के बाद मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

ट्रैक्टर की चपेट में आकर बढ़ई की मौत

ARARIA : फारबिसगंज प्रखंड के सिमराहा थाना क्षेत्र के औराही पूरब वार्ड संख्या एक निवासी सुरेन्द्र शर्मा पिता सीताराम शर्मा की सिरसिया धूमगढ़ के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। फारबिसगंज से बढ़ई का काम कर घर सिमराहा लौटने के क्रम सिरसिया धूमगढ के समीप एक तेज अनियंत्रित ट्रैक्टर के चपेट में आ गया,जिनसे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। परिजन का रो रोकर बुरा हाल है। मृतक का शादी चार वर्ष पूर्व रानीगंज प्रखंड के परमानंदपुर निवासी गाजो शर्मा की पुत्री प्रियंका कुमारी से हुई थी। मृतक की पत्नी गर्भवती है एवं उन्हें दो छोटे छोटे बच्चे में से एक लड़का एक लड़की है। घटना की सूचना मिलने के बाद भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप पटेल मृतक के घर पहुंचकर शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी और ढांढस बंधाते हुए बताया कि मृतक सुरेंद्र प्रतिदिन सिमराहा से फारबिसगंज बढ़ई मिस्त्री का काम करने के लिए जाता था। उन्होंने परिजनों को सरकार से उचित सरकारी अनुग्रह अनुदान राशि दिलाने का भरोसा दिलाया।

ज्वेलरी शॉप लूटकर भाग रहे बदमाशों की फायरिंग में एक की मौत, दो धराए

गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई घटना, भीड़ ने लुटेरों को खदेड़कर दबोचा

- भागते समय बाइक हो गई खराब, लोगों के हत्थे चढ़ गए बदमाश

घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़

PHOTON NEWS GOPALGANJ : गोपालगंज जिले के भोरे थाना स्थित लाला छपरा बाजार में शुक्रवार को ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े लूट हो गई। इसके बाद भागते समय बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। लूटकर भाग रहे बदमाशों को स्थानीय लोगों की भीड़ ने दौड़ाकर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बदमाशों की गोली का निशाना बने मृतक की पहचान कर ली गई है। मृतक डबलू मिश्रा भोरे थाना इलाके के सीसई गांव का रहने वाला था। बताया जाता है कि पांच लुटेरे बाइक पर सवार होकर आए. और स्वर्ण व्यवसायी दीपक वर्मा की ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। अपराधी दुकान में लूटपाट करने के इरादे से घुसे थे।

दिनदहाड़े हुई इस वारदात से बाजार में अफरा-तफरी मच गई। लूटपाट करने के बाद जब अपराधी हथियार लहराते हुए भागने लगे, तभी एक बदमाश की बाइक स्टार्ट नहीं हो पाई, जिस कारण उसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। अन्य बदमाशों को जब स्थानीय लोगों ने उनका पीछा करने का साहस दिखाया, तब अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिससे गोली लगने से डबलू मिश्रा की मौत हो गई।

अपराधियों के भागने के दौरान भीड़ ने साहस का परिचय देते हुए एक अपराधी को पकड़ लिया। पकड़े गए अपराधी की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी, जिसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया. हालांकि, अन्य अपराधी भागने में सफल रहे।

मुआवजे की मांग पर अड़े ग्रामीण : डबलू मिश्रा की मौत की खबर फैलते ही ग्रामीण उग्र हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने सीसई गांव के पास शव को रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और जिला प्रशासन से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। इस संबंध में हथुआ के एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने कहा कि बाइक सवार कुछ बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की है। एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हुई है। मामले की जांच की जा रही है। दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ के आधार पर अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। बाजार में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।

जूट मिल के जमीन घोटाले की फिर से जांच, भू-माफिया पर कसेगा शिकंजा

इसी जमीन को लेकर जल रही जांच

AGENCY KISHANGANJ : शहर से सटे टेउसा पंचायत के शिमलबाड़ी स्थित जूट मिल की जमीन की खरीद-बिक्री में सामने आई अनियमितताओं को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इस बहुचर्चित मामले में नए सिरे से जांच शुरू करने का आदेश दिया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जूट मिल की जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध तरीके से खरीद-बिक्री की गई है। इससे इलाके में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट में यह भी आशंका जताई गई है कि पूरे प्रकरण में संगठित रूप से भू-माफियाओं की संलिप्तता हो सकती है। जांच के दौरान यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि जूट मिल परिसर में सरकारी राशि से निर्मित कई भवन अब गायब हैं। मौके पर केवल कुछ पिलर के अवशेष ही बचे हैं, जो पूरे मामले की कहानी बयां कर रहे हैं। इससे सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग और बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका गहरा गई है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लिए बिना जमीन की खरीद-बिक्री कैसे की गई। आशंका जताई जा रही है कि नियमों को दरकिनार कर बड़े स्तर पर फजीर्वाड़ा किया गया है। जिलाधिकारी विशाल राज ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि पूरे प्रकरण की गहन जांच कराई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जांच में जमीन से जुड़े सभी दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की जाएगी। इसमें यह भी देखा जाएगा कि किन लोगों ने नियमों का उल्लंघन कर इस अवैध खरीद-बिक्री को अंजाम दिया।

अपराध नियंत्रण के लिए एसएसपी ने की सघन वाहन जांच

SARAN : अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के उद्देश्य से वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के निर्देशन में सिवान-सारण मुख्य मार्ग पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान के तहत पुलिस ने विभिन्न संवेदनशील स्थलों पर चेकिंग प्वाइंट बनाकर दोपहिया और चारपहिया वाहनों की गहन तलाशी ली। जांच के दौरान पुलिस बल ने संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने के साथ-साथ अवैध हथियार, शराब और मादक पदार्थों की बरामदगी के लिए विशेष सतर्कता बरती। यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और उन्हें भविष्य में नियमों के पालन की कड़ी हिदायत दी गई। मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपराध पर लगाम लगाने और आम जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए ऐसे अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे।

एनएच-727 पर कार की टक्कर से तीन युवक हो गए घायल

अस्पताल में इलाजरत घायल

BETIA : बेतिया पुलिस जिला के लौरिया थाना क्षेत्र स्थित जिरिया माई स्थान के पास एनएच-727 पर आज सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवक घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तेज गति से आ रही एक स्कॉर्पियो ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को लौरिया रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक डॉ. दिलीप कुमार ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने पर सूरज कुमार और विक्की कुमार को बेहतर इलाज के लिए बेतिया भेज दिया गया, जबकि संदीप कुमार का इलाज स्थानीय स्तर पर जारी है। घायलों की पहचान मानपुर मकरी (थाना बथवरिया) निवासी संदीप (22), सूरज (21) और विक्की (20) के रूप में हुई है। बताया जाता है कि तीनों युवक किसी काम से बीजबनिया गए थे और लौटते समय हादसा हुआ। वहीं, विक्की की 30 अप्रैल को प्रस्तावित शादी को लेकर परिवार में चिंता का माहौल है।

पुलिसकर्मियों के आपत्तिजनक वीडियो मामले में दो गिरफ्तार

SIWAN : पुलिस अधीक्षक पुरन कुमार झा के निर्देश पर सीवान पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। एसपी पुरन कुमार झा ने बताया कि 19 अप्रैल 2026 को पुलिस कर्मियों से संबंधित एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे असामाजिक तत्वों द्वारा तैयार कर प्रसारित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि जांच के क्रम में वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपियों की पहचान कर ली गई, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के अफरोज अली और सरफराज खान के रूप में हुई है। एसपी ने स्पष्ट किया कि इस मामले में संलिप्त अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। दोषियों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कड़ी विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुरन कुमार झा ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक या भ्रामक वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा या प्रसारित करने से बचें। ऐसी गतिविधियां कानूनन अपराध हैं और इसमें शामिल पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अवैध हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार

SIWAN : पुलिस अधीक्षक पुरन कुमार झा के निर्देश पर सीवान पुलिस ने सक्रिय पुलिसिंग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र से अवैध हथियार के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी पुरन कुमार झा ने बताया कि 21 अप्रैल 2026 को सूचना मिली थी कि नगर थाना कांड संख्या 448/26 से संबंधित आरोपी गांधी मैदान के पास देखा गया है। सूचना के आधार पर नगर थाना पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। इस दौरान राम गिरी को एक देशी कट्टा और एक कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए एक अन्य आरोपी अजय प्रसाद का नाम बताया। इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर छापेमारी कर अजय प्रसाद को गिरफ्तार किया और उसके पास से चोरी किया गया कॉपर पाइप बरामद किया। एसपी ने कहा कि इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत कांड दर्ज कर आगे की विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

विरासत संरक्षण में जनभागीदारी जरूरी प्राचीन पांडुलिपियां करें साझा : डीएम

कार्यक्रम में उपस्थित डीएम विवेक रंजन मैत्रेय व अन्य

AGENCY SIWAN : ज्ञान भारत मिशन के तहत ऐतिहासिक पांडुलिपियों के संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान के क्रम में जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय शुक्रवार को सदर प्रखंड के धनौती गांव पहुंचे। उन्होंने कबीर पंथ से जुड़े प्राचीन मठ में संरक्षित पांडुलिपियों का अवलोकन किया और लोगों से इस अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग की अपील की। इस अवसर पर डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने कहा कि हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में आम लोगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिनके पास 75 वर्ष या उससे अधिक पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं, वे उन्हें ज्ञान भारतम् पोर्टल पर अपलोड करें या जिला प्रशासन को सूचित करें, ताकि उनका वैज्ञानिक संरक्षण और डिजिटलीकरण किया जा सके। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम् मिशन के तहत देशभर में भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटलीकरण और अभिलेखीकरण किया जा रहा है, जिससे यह धरोहर शोधार्थियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए सुलभ हो सके। धनौती स्थित कबीर मठ के भ्रमण के दौरान आचार्य महंत गुरु प्रसाद गोस्वामी एवं उत्तराधिकारी महंत आमोदशरण गोस्वामी ने बताया कि यह मठ अत्यंत प्राचीन है और संत कबीर दास के शिष्य भगवान गोस्वामी की कर्मस्थली रहा है। यहीं कबीरदास के बीजक का संकलन किया गया था, जिससे इस स्थल का ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है।

राजनीति मोदी सरकार पर साजिश रचने का दावा कर रहा विपक्ष

दबाव डालकर नीतीश को हटाने का तेजस्वी ने भाजपा पर लगाया आरोप

पत्रकारों को जानकारी देते तेजस्वी यादव

AGENCY PATNA : बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला बोला। विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद सदन से बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अंदर ही अंदर दबाव डालकर, टॉर्चर करके और बेइज्जत कर के हटाया गया है। उन्होंने कहा, इस बात को कौन नहीं जानता है। बिहार में कोई ओरिजनल भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का मुख्यमंत्री बना है क्या?

तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी पहली बार राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के टिकट पर चुनाव लड़े थे और पार्टी की ओर से सचेतक भी बनाए गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि विजय चौधरी पहली बार कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, जबकि बिजेंद्र यादव जनता दल से आए हैं। ऐसे में भाजपा के भीतर भी इस नेतृत्व को लेकर असंतोष होना स्वाभाविक है।

उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी भले ही भाजपा के मुख्यमंत्री हों, लेकिन वे संघ के स्वयंसेवक नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता और उम्र को लेकर भी तंज कसा।

तेजस्वी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि मुख्यमंत्री कितने शिक्षित हैं और उन्होंने कौन-सा कोर्स किया है। उन्होंने कहा कि उनकी डिग्री और उम्र को लेकर भी कई सवाल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी के खिलाफ हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीतिक अस्थिरता पर भी सवाल उठाया।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में पांच सरकारें बनीं, जिससे शासन और विकास कार्य प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, इस साल का 40 प्रतिशत समय तो सरकार बनाने और बदलने में ही बर्बाद हो गया, फिर काम कब हुआ?

तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ना ही था, तो वे चुनाव के समय ही इसकी घोषणा कर सकते थे।

तेजस्वी ने दावा किया कि चुनाव के दौरान कभी यह संकेत नहीं दिया गया, जबकि विपक्ष लगातार कह रहा था कि भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहने देगी। तेजस्वी ने निशांत कुमार के बयान का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी कहा था कि अमित अंकल ने भरोसा दिलाया था कि 2030 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसे में अचानक हुए बदलाव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

घूरना थाना पुलिस और एसएसबी ने 410 किलो गांजा किया बरामद

ARARIA : जिले के घूरना थाना पुलिस और एसएसबी जवानों ने छापेमारी अभियान चलाकर 410 किलो गांजा के साथ एक बाइक जब्त किया।जबकि इस कार्रवाई में तस्कर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार, घूरना पुलिस को बॉर्डर का रास्ते गांजा तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम ने बॉर्डर के समीप नाकेबंदी कर रखा था, इसी बीच घूरना थाना क्षेत्र के डुमरबन्ना वार्ड संख्या 03 के समीप 13 बोरा में 410 किलो गांजा और एक बाइक बरामद किया गया।एसएसबी और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में बीती रात यह कार्रवाई किया गया। तस्कर के द्वारा रात के अंधेरे में नेपाल से भारतीय क्षेत्र माथे पर लाया जा रहा था, तस्कर अधिक संख्या में था जो अंधेरे का लाभ उठाकर नेपाल की तरफ फरार हो गया। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि अज्ञात तस्कर के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

सिंगापुर की तर्ज पर बसेगा हरिहरनाथपुरम : रूडी

सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी

SARAN : सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी की महत्वाकांक्षी परिकल्पना हरिहरनाथपुरम अब धरातल पर उतरने को तैयार है। सांसद रूडी ने सोनपुर को विश्व के सबसे आधुनिक शहर सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने का एक व्यापक रोडमैप साझा किया है। यह परियोजना न केवल बिहार बल्कि देश के सबसे व्यवस्थित सैटेलाइट शहरों में से एक होगी। सांसद रूडी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि यह परियोजना सोनपुर को देश के सबसे व्यवस्थित सैटेलाइट शहरों की श्रेणी में खड़ा कर देगी। इस प्रोजेक्ट के पीछे के तर्क को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि भौगोलिक रूप से सोनपुर और सिंगापुर में समानताएं हैं। जहाँ सिंगापुर का क्षेत्रफल लगभग 733-744 वर्ग किलोमीटर है वहीं सोनपुर का विस्तार अब 680 वर्ग किलोमीटर के दायरे में किया जा रहा है। जिस तरह सिंगापुर अपनी समुद्री तटरेखा के कारण वैश्विक आकर्षण का केंद्र है ठीक उसी तरह सोनपुर गंगा और गंडक जैसी दो विशाल नदियों के संगम पर स्थित है। यह भौगोलिक समानता इसे पर्यटन और व्यापारिक हब बनाने के लिए सर्वोत्तम बनाती है। विगत 5 वर्षों से विशेषज्ञों की टीम के साथ तैयार किए जा रहे इस मास्टर प्लान में कई बड़ी योजनाएं शामिल हैं। सोनपुर में पहले से ही एक आधुनिक हवाई अड्डे का निर्माण स्वीकृत है जो सारण को सीधे वैश्विक हवाई नेटवर्क से जोड़ेगा।

सुरक्षित जीवन की दिशा में: मलेरिया मुक्त भविष्य का संकल्प

सुनील कुमार महला

मलेरिया को आज भी एक सामान्य रोग समझ लिया जाता है, किंतु यह आज भी विश्व की सबसे गंभीर जनस्वास्थ्य समस्याओं में से एक है और हर वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह वायरस से नहीं बल्कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य के शरीर में पहुँचता है।

प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। वास्तव में इस दिवस को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य मलेरिया जैसी जानलेवा, घातक और व्यापक संक्रामक बीमारी के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना, इसके रोकथाम के उपायों को प्रोत्साहित करना, समय पर जाँच एवं उपचार की व्यवस्था पर बल देना तथा वैश्विक स्तर पर इसके उन्मूलन के प्रयासों को गति देना है।

मलेरिया को आज भी एक सामान्य रोग समझ लिया जाता है, किंतु यह आज भी विश्व की सबसे गंभीर जनस्वास्थ्य समस्याओं में से एक है और हर वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह वायरस से नहीं बल्कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य के शरीर में पहुँचता है।पाठक जानते होंगे कि हर मच्छर मलेरिया नहीं फैलाता।मलेरिया शब्द की यदि हम यहां पर बात करें तो यह शब्द इतालवी(इटली) भाषा के माला एरिया से बना है, जिसका अर्थ खराब हवा होता है, क्योंकि प्राचीन काल में लोग मानते थे कि यह बीमारी गंदी या दूषित हवा से फैलती है, जबकि बाद में विज्ञान ने सिद्ध किया कि इसका वास्तविक कारण मच्छर हैं।

पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि मलेरिया कोई नया नहीं बल्कि, यह एक अत्यंत प्राचीन रोग है, जिसका उल्लेख प्राचीन मिस्र, भारत तथा चीन के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। संक्रमित मच्छर के काटने पर प्लाज्मोडियम परजीवी रक्त में प्रवेश कर लाल रक्त कोशिकाओं में बहुगुणित होने लगता है, जिससे रक्तहीनता (एनीमिया), कमजोरी और अन्य जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं। बहरहाल, इसके प्रमुख लक्षणों की यदि हम यहां पर बात करें तो इसके प्रमुख लक्षणों में क्रमशः तेज बुखार, ठंड लगना, कंपकंपी, सिरदर्द, मतली, उल्टी, अत्यधिक पसीना आना, चक्कर आना, साँस फूलना, तेज नाड़ी, थकान, कमजोरी तथा जुकाम जैसी अनुभूति शामिल हैं। गंभीर अवस्था में रोगी मूर्च्छा तक में जा सकता है और व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। कुछ लोगों में इसके लक्षण देर से प्रकट होते हैं, किंतु छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों में यह शीघ्र और अधिक घातक रूप ले सकता है। रोगी के ठीक होने के बाद भी यह रोग पुनः हो सकता है। वर्षा ऋतु में या वर्षा के बाद जब घरों, गलियों और आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा हो जाता है, तब मच्छरों का प्रजनन तेजी से होता है और संक्रमण का प्रसार बढ़ जाता है। यही कारण है कि स्वच्छता और जलभराव रोकना मलेरिया नियंत्रण का अत्यंत महत्त्वपूर्ण उपाय माना जाता है। यह रोग मुख्य रूप से

अफ्रीका, एशिया, अमेरिका तथा अन्य उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल होती है। मलेरिया गरीब क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, क्योंकि वहाँ स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं, सुरक्षित आवास और रोकथाम के संसाधनों की कमी होती है।

बहरहाल, यहां पाठकों को जानकारी देता चलूं कि वर्ष 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र में इसे मनाने का निर्णय लिया गया था और पहला आधिकारिक विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था।हर साल इस दिवस की एक थीम रखी जाती है और वर्ष 2025 की थीम-मलेरिया का अंत हमसे होगाः पुनर्निवेश करें, नए तरीके सोचें और प्रयासों को फिर से प्रज्वलित करें। रखी गई थी ,जिसका मतलब है कि मलेरिया का अंत हमारे अपने प्रयासों से ही संभव है। सरल शब्दों में कहें तो मलेरिया नियंत्रण और अनुसंधान में फिर से अधिक संसाधन, धन और ध्यान लगाना होगा,इस पर नियंत्रण के लिए हमें नए सिरे से सोचना होगा। हमें पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ नए, प्रभावी और आधुनिक उपाय अपनाने होंगे तथा मलेरिया उन्मूलन के वैश्विक प्रयासों में नई ऊर्जा और उत्साह पैदा करना होगा। वहीं इस वर्ष यानी कि वर्ष 2026 में इसकी थीम-मलेरिया समाप्त करने के लिए प्रेरितः अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा। रखी गई है। वास्तव में इसका सीधा सा संदेश यह है कि अवसर और साधन मौजूद हैं, इसलिए अब देरी नहीं, बल्कि निर्णायक कार्रवाई का समय है।

हाल फिलहाल, यदि हम यहां पर आंकड़ों की बात करें तो वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामले लगभग 28.2 करोड़ तक पहुँच चुके हैं और लगभग 6.10 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें अधिकांश पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। पूर्व की विश्व मलेरिया रिपोर्टों में यह तथ्य भी सामने आया कि कुछ वर्षों में हर 50 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु मलेरिया के कारण हो रही थी। वर्ष 2020 में विश्व स्तर पर 6,27,000 लोगों की मृत्यु मलेरिया के कारण दर्ज की गई थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी।इन सभी के बीच राहत की बात यह है कि दुनिया के 47 देश मलेरिया मुक्त घोषित किए जा चुके हैं और चीन को भी मलेरिया मुक्त देश का दर्जा प्राप्त हुआ है। वहीं पर, भारत की स्थिति पिछले वर्षों में उत्साहजनक रही है। देश ने एक दशक में मलेरिया मामलों में लगभग 80 प्रतिशत कमी दर्ज की है,यह काबिले-तारीफ है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि भारत सरकार ने 2027 तक मलेरिया मुक्त भारत और 2030 तक पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। अतीत में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्य मलेरिया से अधिक प्रभावित रहे, विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरूआत में भारत की लगभग एक चौथाई आबादी मलेरिया से प्रभावित बताई जाती है। 1935 के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत को मलेरिया के कारण प्रतिवर्ष भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। भारत सरकार ने 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया, जो अत्यंत सफल रहा, और 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। निरंतर सरकारी प्रयासों, चिकित्सा सेवाओं, दवाओं और जागरूकता अभियानों से रोगियों की संख्या में भारी कमी आई, किंतु अभी भी पूर्ण सफलता शेष है। मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग, घर के आसपास पानी जमा न होने देना, जल टंकियों को ढककर रखना, खड़े पानी को सुखाना या बहाना, पानी की सतह पर तेल डालना जिससे लार्वा साँस न ले सके, नियमित साफ-सफाई, पूरी बाँह के कपड़े पहनना, समय पर जाँच, डॉक्टर की सलाह से दवा लेना तथा कीटनाशकों का छिड़काव करना अत्यंत आवश्यक है।

बहुत कम लोग ही यह बात जानते होंगे कि सेनाओं और सुरक्षा बलों में मलेरिया रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उनकी तैनाती प्रायः जंगलों, सीमावर्ती क्षेत्रों और मच्छर-बहुल स्थानों पर होती है, इसलिए मच्छरदानी का उपयोग वहाँ अनिवार्य माना जाता है। मलेरिया का उपचार कुनैन तथा आर्टिमीसिनिन जैसी दवाओं से किया जाता है। कुनैन सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। आरटीएस ,एसऔर आर-21 ऐसे टीके हैं जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दी है और जिनसे विशेषकर बच्चों की सुरक्षा में सहायता मिली है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मच्छर नियंत्रण के लिए डीडीटी (डाइक्लोरो-डाइफेनाइल-ट्राइक्लोरोइथेन) कभी अत्यंत प्रभावी हथियार सिद्ध हुआ था। यह पहला आधुनिक कीटनाशक माना जाता है। इसका संश्लेषण 1874 में ऑस्ट्रिया के रसायनज्ञ ओथमार जीडलर ने किया था तथा इसके कीटनाशी गुणों की खोज 1939 में पॉल हरमन मुलर ने की थी, जिन्हें 1948 में नोबेल पुरस्कार मिला। गौरतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों और आम जनता को मलेरिया तथा टाइफस से बचाने के लिए इसका व्यापक उपयोग हुआ। बाद में पर्यावरणीय प्रभावों के कारण इसके उपयोग पर नियंत्रण लगाया गया, किंतु कुछ परिस्थितियों में मलेरिया नियंत्रण हेतु सीमित उपयोग को स्वीकृति दी गई। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गर्मी, मच्छरों में कीटनाशक प्रतिरोधक क्षमता, परजीवियों में दवा प्रतिरोध, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, गरीबी, पर्याप्त कोष का अभाव, सामुदायिक भागीदारी की कमी, समय पर छिड़काव न होना, रोग की पहचान में देरी तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक चिकित्सा सुविधा न पहुँच पाना मलेरिया उन्मूलन की बड़ी बाधाएँ हैं। इसलिए आवश्यक है कि जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, रेडियो, फिल्म, विद्यालयों और सामाजिक माध्यमों से जानकारी पहुँचाई जाए, गरीबों को स्वास्थ्य संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ, स्वच्छता पर बल दिया जाए और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। अंत में यही कहूंगा कि विश्व मलेरिया दिवस हमें यह संदेश देता है कि यदि सरकार, समाज, चिकित्सा संस्थान और प्रत्येक नागरिक सामूहिक संकल्प के साथ आगे आएँ, तो मलेरिया जैसी बीमारी को हराकर मलेरिया मुक्त भारत और मलेरिया मुक्त विश्व का सपना अवश्य साकार किया जा सकता है।

संपादकीय

जीवनशैली के रोग

निस्संदेह, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की वह रिपोर्ट राष्ट्रीय चिंता बढ़ाने वाली है कि देश की पचास फीसदी आबादी जीवनशैली से जुड़े रोगों से ग्रस्त-त्रस्त है। यह भी फिक्र बढ़ाने वाला है कि एक दशक पहले देश में खान-पान, जीवन व्यवहार व तनाव से उपजे रोगों का प्रतिशत जहां 31 था, वो अब पचास फीसदी तक जा पहुंचा है। वहीं एक अच्छी बात यह है कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार व नये शोध अनुसंधान के चलते संक्रामक रोगों का प्रतिशत घटा है। लेकिन हमारे खानपान व जीवन व्यवहार में तेजी से आ रहे बदलावों के चलते लोग मोटापे, मधुमेह, तनाव व उच्च रक्तचाप जैसे रोगों के शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते जानलेवा संकट भी बढ़ रहा है। हमें स्वीकार करना होगा कि आजादी के बाद देश में आम आदमी के जीवन स्तर में किसी न किसी तरह सकारात्मक बदलाव आया है, जिसके चलते जीवनशैली भी बदली है। लेकिन पौष्टिक व शरीर की जरूरतों के अनुकूल भोजन न करने, शारीरिक निष्क्रियता, स्क्रीन टाइम बढ़ने से नींद की कमी आदि अनेक ऐसे कारण हैं जो इन रोगों के वाहक बनते हैं। इसमें आनुवंशिक रोगों की भी भूमिका है। धीरे-धीरे शरीर को खोखला करने वाले ये रोग कालांतर जानलेवा बन जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन भी चिंता जता रहे हैं कि भारत में विभिन्न रोगों से मरने वाले ज्यादातर लोगों की मौत की वजह संक्रामक रोग के बजाय जीवनशैली से जुड़े रोग हैं। जो हमारी गभीर चिंता का विषय होना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चिकित्सा विज्ञान की आशातीत प्रगति के चलते आम भारतीय की जीवन प्रत्याशा में इजाफा हुआ है, लेकिन जीवनशैली से जुड़े रोगों का बढ़ना इस कामयाबी पर पानी फेरने जैसा है। यही वजह है कि देश में स्वास्थ्य बीमा कारोबार में तेजी आई है, यह तेजी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। लेकिन ये बीमा कंपनियां रोग से बचाव में मदद करने के बजाय व्यक्ति के रोगों के इलाज को प्राथमिकता देती हैं। हालांकि, देश में जीवनशैली से जुड़े रोगों से बचाव के लिये जागरूकता जरूर आई है। जिसके लिये राजग सरकार को श्रेय देना होगा। प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग का दुनिया में व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ है। यह जागरूकता भारत में भी है। लेकिन बड़ी आबादी अब भी इससे दूर है। प्रधानमंत्री ह्यमन की बातह्व रेडियो कार्यक्रम व अन्य मंचों से मोटापे से बचाव और खानपान में मिलेट अपनाने पर अक्सर बल देते नजर आते हैं। लेकिन इस पर सकारात्मक प्रतिसाद अपेक्षित अनुपात में नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि लोगों को महंगा इलाज कराने को बाध्य होना पड़ता है। विडंबना है कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसे रोगों से राहत के लिये डॉक्टर जीवनभर दवा खाने को कहते हैं। तमाम लोग निजी अस्पतालों में हृदयरोग आदि के महंगे इलाज से गरीबी की दलदल में फंस जाते हैं। कोरोना संकट के सबक हमें याद रखने चाहिए, जब लोगों ने जेवर, जमीन व मकान तक गिरवी रखकर अपना उपचार कराया। लेकिन यदि लोग शारीरिक सक्रियता बढ़ाएं, योग, ध्यान और व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाएं तो इन रोगों से बच सकते हैं।

चिंतन-मनन

ईश्वर का स्वरूप क्या है?

पहले अपने स्वरूप को जानें

एक महात्मा से किसी ने पूछा- ईश्वर का स्वरूप क्या है?

महात्मा ने उसी से पूछ दिया-तुम अपना स्वरूप जानते हो?

वह बोला- नहीं जानता।

तब महात्मा ने कहा- अपने स्वरूप को जानते नहीं जो साढ़े तीन हाथ के शरीर में मैं-मैं कर रहा है और संपूर्ण विश्व के अधिष्ठान परमात्मा को जानने चले हो। पहले अपने को जान लो, तब परमात्मा को तुरंत जान जाओगे। एक व्यक्ति एक वस्तु को दूरबीन से देख रहा है। यदि उसे यह नहीं ज्ञान है कि वह यंत्र वस्तु का आकार कितना बड़ा करके दिखलाता है, तो उसे वस्तु का आकार कितना बड़ा करके दिखलाता है, तो उसे वस्तु के सही स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा?

अतः अपने यंत्र के विषय में पहले जानना आवश्यक है। हमारा ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा संसार दिखलाता है। हम यह नहीं जानते कि वह दिखाने वाला हमें यह संसार यथावत? ही दिखलाता है या घटा-बढ़ाकर या विकृत करके दिखलाता है। गुलाब को नेत्र कहते हैं- यह गुलाबी है। नासिका कहती है- यह इसमें एक प्रिय सुगंध है। त्वचा कहती है- यह कोमल और शीतल है। चखने पर मालूम पड़ेगा कि इसका स्वाद कैसा है। पूरी बात कोई इंद्री नहीं बतलाती। सब इन्द्रियां मिलकर भी वस्तु के पूरे स्वभाव को नहीं बतला पातीं।

आचार्य महाश्रमण की निर्गुण-चेतना से विश्व-शांति की नई दिशा

ललित गर्ग

मानव इतिहास के इस अशांत और संक्रमणकालीन दौर में जब विश्व का परिदृश्य युद्ध, हिंसा, आतंकवाद और वैचारिक टकरावों से आच्छादित है, तब शांति, सह-अस्तित्व और मानवीय मूल्यों की पुकार पहले से कहीं अधिक तीव्र हो उठी है। ऐसे समय में आचार्य महाश्रमण एक ऐसे आध्यात्मिक प्रकाशस्तंभ के रूप में उभरते हैं, जिनका चिंतन केवल किसी एक पंथ, सम्प्रदाय या राष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के कल्याण का व्यापक दृष्टिकोण अपने भीतर समेटे हुए है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व 'निर्गुण रंगी चदरिया' की उस अनुभूति को मूर्त करता है, जो गुणों के पार जाकर आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थित होने का संदेश देती है। भगवद्गीता में अर्जुन को दिए गए श्रीकृष्ण के उपदेश 'त्रिगुणातीत बन जा' के अनुरूप आचार्य महाश्रमण का जीवन एक सजीव उदाहरण बनकर सामने आता है। उन्होंने सत्व, रज और तम के बंधनों को पार कर उस निर्गुण अवस्था को साधने का प्रयास किया है, जहाँ व्यक्ति न केवल आत्मबोध को प्राप्त करता है, बल्कि समष्टि के कल्याण का माध्यम भी बन जाता है। उनका यह दृष्टिकोण केवल दार्शनिक विमर्श नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन में उतरा हुआ सत्य है। उनकी साधना 'सत्य की पूजा' नहीं करती, बल्कि 'सत्य की शल्य-चिकित्सा' करती है अर्थात् वे सत्य को केवल स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसकी गहराई में उतरकर उसे परिष्कृत करते हैं।

आचार्य महाश्रमण का जीवन 'रहें भीतर, जीएँ बाहर' के सूत्र पर आधारित है। यह सूत्र आधुनिक जीवन की जटिलताओं में संतुलन स्थापित करने का एक अद्वितीय मार्ग प्रस्तुत करता है। आज का मनुष्य बाहरी उपलब्धियों की दौड़ में अपने भीतर के शून्य को अनदेखा कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप तनाव, असंतोष और हिंसा का जन्म होता है। आचार्य महाश्रमण का चिंतन इस अंतर्विरोध को समाप्त करने का प्रयास करता है। वे सिखाते हैं कि यदि भीतर शांति और संतुलन है, तो बाहर का जीवन स्वतः ही सुव्यवस्थित हो जाता है। यही कारण है कि उनकी साधना केवल आत्मिक उन्नति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी आधार बनती है। उनकी 'अहिंसा यात्रा' आज के समय की एक ऐतिहासिक और युगान्तरकारी पहल है, जो हमें दांडी यात्रा और भूदान आंदोलन की याद दिलाती है। यह यात्रा केवल एक पदयात्रा नहीं, बल्कि विचारों की क्रांति है-एक ऐसी क्रांति, जो हथियारों से नहीं, बल्कि संवाद, संवेदना और संस्कारों से संचालित होती है। देश-विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल चलकर उन्होंने लाखों लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया, उन्हें नशामुक्ति, सदाचार, नैतिकता और अहिंसा के मार्ग पर अग्रसर किया। आज जब विश्व के अनेक देश युद्ध और आतंकवाद की विभीषिका से जूझ रहे हैं, तब आचार्य महाश्रमण का यह प्रयास एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करता है-एक ऐसा मार्ग, जहाँ शांति केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक संभावना बन जाती है। उनकी दृष्टि 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को साकार करती है, जहाँ सम्पूर्ण विश्व एक परिवार के रूप में देखा जाता है। वे किसी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, वर्ग या क्षेत्र के आधार पर नहीं, बल्कि उसके भीतर विद्यमान गुणों के आधार पर आंकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति और सहयोग की नींव भी रखता है। आज जब पहचान की राजनीति और सांस्कृतिक विभाजन समाज को खंडित कर रहे हैं, तब आचार्य महाश्रमण का यह समन्वयवादी दृष्टिकोण अत्यंत प्रासंगिक हो उठता है।

आचार्य महाश्रमण की सादगी, विनम्रता और अनुशासन उनके व्यक्तित्व की विशिष्ट पहचान हैं। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जैसे महान आचार्यों के सान्निध्य में विकसित उनका जीवन एक ऐसी परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, जो आत्मानुशासन और सेवा को सर्वोच्च मूल्य मानती है। बाल्यावस्था में ही दीक्षा लेकर उन्होंने जिस तप, त्याग और समर्पण का मार्ग अपनाया, वह आज के भौतिकतावादी युग में एक प्रेरणास्रोत है। उनकी जीवन यात्रा मोहनलाल से मुनि मुदितकुमार, फिर महाश्रमण और अंततः आचार्य बनने तक एक ऐसी साधना गाथा है, जो यह सिद्ध करती है कि आत्मबल और संकल्प से किसी भी ऊँचाई को प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य महाश्रमण की बौद्धिक प्रतिभा भी उतनी ही प्रभावशाली है, जितनी उनकी आध्यात्मिक साधना। उत्तराध्ययन सूत्र और भगवद्गीता जैसे महान ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन कर उन्होंने यह सिद्ध किया है कि सत्य किसी एक परंपरा का एकाधिकार नहीं है। उनके प्रवचनों का संकलन 'सुखी बनो' इस दृष्टि का सशक्त उदाहरण है, जिसमें उन्होंने जीवन को सरल, सार्थक और संतुलित बनाने के सूत्र प्रस्तुत किए हैं। उनका चिंतन आगम, दर्शन, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र जैसे विविध क्षेत्रों को समाहित करता है, जिससे उनका व्यक्तित्व एक बहुआयामी मनीषी के रूप में उभरता है।

आज के वैश्विक परिदृश्य में, जहाँ युद्ध की विभीषिका और परमाणु हथियारों की होड़ मानव अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी है, वहाँ आचार्य महाश्रमण का 'अहिंसा का शंखनाद' एक जीवनदायी संदेश के रूप में सामने आता है। उनका यह विश्वास कि 'अहिंसा केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है', हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या वास्तव में हिंसा के माध्यम से स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है? उनका उत्तर स्पष्ट है-नहीं। शांति का मार्ग केवल संवाद, सहिष्णुता और करुणा से होकर गुजरता है। उनके प्रयासों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्रतिदिन नई ऊर्जा और संकल्प के साथ वे मानव उत्थान के कार्यों में जुटे रहते हैं। उनकी दिनचर्या, उनका अनुशासन और उनका समर्पण यह दशार्ता है कि सच्चा नेतृत्व वही है, जो अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करे। उनके नेतृत्व में तेरापंथ धर्मसंघ न केवल संगठित और सशक्त हुआ है, बल्कि उसने समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और नैतिक जागरण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

निश्चित तौर पर जैन धर्म के महान तपस्वी, अनुशासनप्रिय, दूरदर्शी और तेजस्वी आचार्य महाश्रमण के सान्निध्य में आध्यात्मिकता और आधुनिकता का अद्भुत संगम बनी जैन विश्व भारती में इस वर्ष योगक्षेम वर्ष के रूप में एक नया आध्यात्मिक इतिहास रचा जा रहा है, आध्यात्मिक प्रशिक्षण की एक नई परंपरा विकसित की जा रही है। देशभर में विचरण करने वाले साधु-संतों को एक जगह बुलाकर आचार्य महाश्रमण उन्हें अध्यात्म का प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह वास्तव में जैन धर्म का एक अनूठा और संभवतः पहला ऐसा व्यापक प्रयोग है, जिसमें वर्षभर तक साधु-साध्वियों के साथ-साथ श्रावक समाज को भी गहन एवं व्यवस्थित रूप से जैन एवं तेरापंथ दर्शन, अध्यात्म, योग, ध्यान, स्वाध्याय, संयम और जीवन मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आचार्य श्री महाश्रमण की दूरदर्शी सोच, उनका अनुशासन, उनका साधना-प्रधान जीवन और समाज को आध्यात्मिक दिशा देने का उनका प्रयास वास्तव में अद्वितीय है। उन्होंने धर्म को केवल परंपरा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जीवन और समाज से जोड़ा। समय को बांधने की अद्भुत खूबी है उनमें। कम समय में अधिक काम। वह भी इतनी सहजता और निर्भरता से सम्पादित कर लेने की सामर्थ्य, उनकी कार्य व्यस्तता कभी व्यग्रता में नहीं बदलती। यह सब इसीलिए हो सकता है कि उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति निवृत्ति से निथर कर आती है। उनकी क्रियाशीलता आंतरिक स्थिरता स्थितप्रज्ञता से अभिनिःसृत होती है।

बंपर वोटिंग का संदेश: क्या ज्यादा मतदान सत्ता की वापसी का संकेत है या बदलाव की आहट–जनता की चुप्पी में छिपा जनादेश

कांतिलाल मांडोत

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता और परिपक्वता को एक बार फिर रेखांकित किया है। भीषण गर्मी, लंबी कतारें और कई जगहों पर तनावपूर्ण माहौल के बावजूद जिस तरह मतदाताओं ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वह सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतांत्रिक भागीदारी का सशक्त प्रदर्शन है। यह सवाल अब स्वाभाविक रूप से उठता है कि इतनी भारी वोटिंग का अर्थ क्या है–क्या यह सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जनसमर्थन का संकेत है या फिर परिवर्तन की इच्छा का प्रतीक?

इतिहास बताता है कि अधिक मतदान को एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता। कई बार ज्यादा मतदान सत्ता में बैठे दल के पक्ष में गया है, तो कई बार यह बदलाव की लहर का संकेत भी बना है। इसलिए इस बार भी केवल प्रतिशत के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि जब सामान्य से कहीं अधिक मतदाता मतदान के लिए निकलते हैं, तो उसके पीछे कोई न कोई मजबूत भावनात्मक या राजनीतिक कारण जरूर होता है।

पश्चिम बंगाल में इस बार मतदान का प्रतिशत 90% के पार चला गया, जो अपने आप में एक असाधारण स्थिति है। यहां चुनाव हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील और कभी-कभी हिंसक भी रहे हैं। इस बार भी छिटपुट हिंसा की घटनाएं सामने आईं, लेकिन इसके बावजूद लोगों का बड़ी संख्या में मतदान करना यह दशार्ता है कि वे अपने वोट के महत्व को समझते हैं और किसी भी परिस्थिति में लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं। यहां मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, और दोनों ही दल इस भारी मतदान को अपने-अपने पक्ष में बता रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि यह मतदान उनके खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों और कथित मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में जनता की प्रतिक्रिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे 'जनता की आवाज' बताया है, जो उनके अनुसार बाहरी हस्तक्षेप और राजनीतिक दबाव के खिलाफ है। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी इसे 'परिवर्तन की लहर' के रूप में पेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में दावा किया है कि जहां ज्यादा मतदान हुआ है, वहां भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है।

तमिलनाडु की स्थिति थोड़ी अलग लेकिन उतनी ही रोचक है। यहां परंपरागत रूप से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के बीच सीधी टक्कर रहती है। इस बार भी यही मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन अभिनेता विजय की नई पार्टी ने समीकरणों को थोड़ा जटिल बना दिया है। रिकॉर्ड मतदान को यहां स्पष्ट जनादेश की संभावना के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर तमिलनाडु में जब मतदान प्रतिशत बहुत अधिक होता है, तो मतदाता किसी एक पक्ष में स्पष्ट रूप से झुकाव दिखाते हैं।

इस बार के चुनावों में एक और महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, कई क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया है। यह केवल संख्या का मामला नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव का संकेत भी है। महिलाएं अब केवल मतदाता नहीं रहीं, बल्कि वे निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। उनके मुद्दे–महंगाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार की आर्थिक स्थिति–चुनावी विमर्श के केंद्र में आ चुके हैं।

अगर मुद्दों की बात करें तो दोनों राज्यों में स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के मुद्दे प्रभावी रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार के आरोप, केंद्र-राज्य संबंध और पहचान की राजनीति प्रमुख मुद्दे रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में विकास, रोजगार, शिक्षा और क्षेत्रीय अस्मिता जैसे विषयों ने मतदाताओं को प्रभावित किया है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे राष्ट्रीय मुद्दों का असर भी दोनों राज्यों में साफ दिखाई देता है।

बंपर वोटिंग का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी होता है। जब लोग बड़ी संख्या में मतदान करने निकलते हैं, तो यह

संकेत होता है कि वे मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं या फिर वे किसी बदलाव को लेकर उत्साहित हैं। यह असंतोष भी हो सकता है और उम्मीद भी। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि यह मतदान किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन इतना तय है कि यह सामान्य चुनाव नहीं है।

राजनीतिक दलों के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन असली तस्वीर 4 मई को सामने आएगी जब नतीजे घोषित होंगे। तब यह स्पष्ट होगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया और किसे नकार दिया। फिलहाल, यह कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह जनता की आकांक्षाओं, उम्मीदों और असंतोष का प्रतिबिंब है।

अंततः, बंपर वोटिंग लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यह दशार्ता है कि जनता जागरूक है, सक्रिय है और अपने अधिकारों के प्रति गंभीर है। चाहे परिणाम कुछ भी हों, यह भागीदारी ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

Constitutional clocks that just start ticking

The failure of the Constitution (131st Amendment) Bill to garner the requisite two-thirds majority in the Lok Sabha, and the consequential withdrawal of the Delimitation Bill and Union Territories Laws (Amendment) Bill, are being celebrated in some quarters as a victory for fairer federalism. It is nothing of the sort. On careful constitutional reading, it is the beginning of a process far more disruptive than the passage of the Bills would have been. The public debate has been charged with rhetoric. What will actually unfold has found little mention.Some constitutional history is essential. The current Lok Sabha seat allocation—39 for Tamil Nadu, 20 for Kerala, 28 for Karnataka, 25 each for Andhra Pradesh and Rajasthan, 80 for Uttar Pradesh—is derived from the 1971 census. The Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 froze the allocation of Lok Sabha seats on the basis of 1971 population figures. The Constitution (84th Amendment) Act, 2001 extended that freeze—keeping every state's proportional share as it was in 1971—until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 are published. The Kuldip Singh Delimitation Commission, constituted in 2002, worked entirely within this mandate. It redrew the internal boundaries of Lok Sabha and Vidhan Sabha constituencies using 2001 census figures, but was constitutionally prohibited from altering a state's seat total.That freeze is now imminently approaching its constitutionally mandated expiry. It lifts automatically—without any further parliamentary action, without any constitutional amendment—upon the publication of the relevant figures for the first census taken after 2026. Once the figures of the ongoing census are published—realistically, between 2029 and 2031—the freeze expires of its own terms under Article 82. The Delimitation Commission then constituted will work on pure population proportionality under the unamended Article 81(2)(a). Every state's Lok Sabha allocation will reflect its share of the national population as recorded in the post-2026 census.

This is where the arithmetic becomes uncomfortable. Between 1971 and the present, the demographic divergence between the north and the south has been profound. States that invested in family planning and human development—Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana—controlled their population growth. States that did not—UP, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan—grew substantially faster. Under strict population proportionality, the political consequence is a structural shift in representation to the north that no political protest can reverse without a constitutional amendment. To illustrate: on current population estimates, one Lok Sabha seat in UP represents approximately 30 lakh people; in Tamil Nadu, approximately 20 to 21 lakh; in Kerala, approximately 19 lakh. Under post-2026 proportionality,

that differential disappears and, with it, the south's representational advantage.Now consider what the 131st Amendment Bill, had it passed, would have delivered. It locked in the 2011 census—not the post-2026 one—as the operative basis for delimitation through a specific definitional mechanism in the Delimitation Bill, 2026. On 2011 figures, Tamil Nadu would have received approximately 57 Lok Sabha seats, an increase of 18 from its current 39. Kerala would have gone from 20 to approximately 29 and Karnataka from 28 to approximately 41. Not one southern state would have lost a single seat. Their proportional share would have declined negligibly as the overall House expanded, but their absolute representation would have grown substantially. Additionally, a constitutional provision prescribing minimum and maximum seat ranges for every state could have given the southern states a guaranteed floor written into the Constitution itself, immune to future census arithmetic.That protection is now not in place.

Why J&K wetlands are at a tipping point

Their degradation is fast leading to a crisis of water security, livelihoods and survival

The Shallabugh wetland crisis has taken an unsettling form. Though water is still visible, life within it is disappearing. Fish populations have dwindled to alarming levels, and with them, the birds that once thrived here. Cormorants and other fish-eating species are no longer frequent visitors. What remains is a quiet, stagnant expanse that appears alive but is ecologically hollow.At a time when heatwaves are growing more intense, and weather patterns are increasingly unpredictable, the degradation of wetlands is no longer a distant environmental concern. It is fast becoming a crisis of water security, livelihoods and survival. A recent report by the Comptroller and Auditor General (CAG) casts light on the declining wetlands of Jammu and Kashmir, presenting not just an audit of governance but also a troubling portrait of ecological decline. What emerges is a story of neglect, fragmented policies and mounting climate stress that together threaten one of the Himalayan region's most vital natural systems.

The scale of loss is staggering. Of the 697 lakes recorded in 1967, nearly three-quarters have either vanished or shrunk significantly. This is more than a numerical decline. It represents the steady erasure of Kashmir's hydrological identity, where lakes and wetlands have long shaped culture, ecology and daily life.

These water bodies are not isolated features. Wetlands such as Shallabugh, Hokersar and Anchar form an intricate network linked to rivers, floodplains and underground aquifers. Their decline signals a deeper disruption in the natural processes that sustain the region. Experts point to pollution, nutrient overload and habitat disruption as the likely causes behind the collapse of aquatic life. When fish vanish, the ripple effect moves upward through the food chain, leaving birds without sustenance and breaking ecological links that once held the system together.Plus, rapid development has introduced new pressures. The expansion of roads, tunnels, hotels and resorts across Jammu and Kashmir is reshaping the landscape at an unprecedented pace. While tourism is often promoted as an economic lifeline, its unregulated growth has placed immense strain on fragile water systems.

Construction disrupts natural drainage channels and increases sediment flow into wetlands. Waste generated by tourists often finds its way into lakes and marshes. In a region where water defines both environment and economy, such patterns raise serious questions about sustainability.The transformation of land use has also sidelined traditional communities. Indigenous pastoralists, who have historically managed rangelands through sustainable practices, are facing increasing restrictions. These rangelands contribute significantly to the local economy and play a vital ecological role by regulating water flow, conserving soil and supporting biodiversity.Yet, many landscapes are being repurposed for tourism. This shift not only disrupts livelihoods but also weakens the ecological balance that supports wetland health. Changes in grazing patterns and land cover can alter runoff and reduce groundwater recharge, compounding the stress on already shrinking wetlands.The report also underscores institutional failure. Despite national wetland regulations requiring the establishment of dedicated conservation authorities, J&K's response has been limited. The absence of a strong wetlands authority has left conservation efforts fragmented and ineffective.Multiple government departments share responsibility for wetlands, but coordination among them remains weak. Irrigation, tourism, urban development and environmental

agencies often operate with conflicting priorities. In some cases, conservation measures are undermined by parallel approvals for construction in sensitive areas. The result is a governance vacuum where ecological concerns are repeatedly pushed aside.

Even within existing conservation structures, priorities appear uneven. The Lakes Conservation and Management Authority has focussed on high-profile water bodies such as the Dal Lake. Lakes like Anchar, despite their ecological and economic importance, have suffered severe degradation. This selective attention overlooks the interconnected nature of the water systems. The decline of one lake affects others, making isolated interventions insufficient. A broader, landscape-level approach is essential to restore balance.Overlaying these human-driven challenges is the accelerating force of climate change. Rising temperatures, erratic rainfall and more frequent heatwaves are amplifying the vulnerability of wetlands. These ecosystems play a crucial role in moderating climate by storing water, recharging aquifers and acting as buffers against floods. As wetlands disappear, so does their ability to regulate temperature and absorb excess water. Urban areas like Srinagar are experiencing increased heat retention linked to the loss of natural water bodies and spread of concrete surfaces.Civil society groups have stepped in to document and raise awareness. The School for Rural Development and Environment has surveyed more than 50 wetlands across the region, highlighting patterns of degradation through fieldwork and community engagement. Their findings, shared with the auditing process, have helped bring local realities into the national spotlight.Voices such as journalist Fayaz Bukhari and others have drawn attention to the issue, ensuring that the decline of wetlands is not overlooked in policy discussions. The audit report reflects this convergence of institutional review and grassroots observation, lending weight to its conclusions.The consequences of wetland loss extend beyond environmental concerns. Groundwater levels are falling as recharge systems weaken. Flood risks are rising in the absence of natural buffers. Biodiversity is declining, with species losing critical habitats. Communities dependent on fishing, farming and tourism are facing economic uncertainty. The reduction in carbon storage further contributes to global warming.

Wetlands, often dismissed as wastelands, are in fact essential life-support systems. Their degradation is a direct threat to human well-being. The report calls for urgent and coordinated action. Establishing a fully functional Wetlands Authority, enforcing regulations and adopting integrated management approaches are critical first steps.Equally important is the need to regulate tourism, protect rangelands and support indigenous communities, whose knowledge and practices have long sustained these ecosystems.Improved waste management, pollution control and community-led conservation efforts could help reverse some of the damage. However, time is crucial. Delayed action risks pushing these ecosystems beyond recovery. The wetlands of Jammu and Kashmir stand at a tipping point. Their decline reflects a broader crisis where environmental stewardship has struggled to keep pace with development and climate change. What is at stake is not only the health of ecosystems but also the future of communities that depend on them.

VIP arrogance: Influence too often trumps law & fairness

The reported taunt — "If your daddy has guts…" — is a chilling reminder of how casually some in public life treat the institutions meant to uphold the law

THE ugly episode in Madhya Pradesh, where BJP MLA Pritam Lodhi allegedly threatened police officers after his son was accused of injuring five people on the road with his speedily driven SUV, is more than a local controversy. The reported taunt — "If your daddy has guts…" — is a chilling reminder of how casually some in public life treat the institutions meant to uphold the law. What should have remained a straightforward road accident investigation has exposed a deeper malaise of the belief that political power can browbeat the police and bend accountability. Rather than allowing the law to take its course, the police were publicly challenged, warned and mocked. Such behaviour sends a dangerous signal — that rules apply only to the powerless.Sadly, this is not an isolated incident, as some similar cases of high-handedness from last year show. In Rajasthan, an MLA was reported threatening civic officials with violence from

inside a police station itself. In Bihar, a legislator faced allegations of abusing and intimidating a panchayat official over the phone. In Uttar Pradesh, the son of a political figure was seen arguing with traffic police after being asked to move a vehicle blocking the road. Different states, different parties, same entitlement.

The damage extends beyond bureaucracy. Citizens watching such scenes conclude that justice is negotiable, that connections matter more than conduct and that public institutions can be bullied into submission. Democracy then becomes hollow theatre. Political parties cannot escape blame. Too often, they condemn arrogance in rivals while protecting it in their own ranks. Real accountability requires more than embarrassment after a viral video. It demands swift legal action, internal discipline, and visible support for officers performing lawful duty. The rule of law is tested not when the weak are prosecuted, but when the powerful are restrained.

Strong headwinds test India

Where traditional politicians trade in credibility (fragile or fluctuating), Trump deals in defiance. He pre-bunks every critique, pre-labels every attack, and also pre-loads every scandal into a persecution playlist

INDIA is in the middle of yet another electoral cycle. States are going in for Assembly elections and the issues raised are both state-level and national. Amid the polls, the Union government hastily tried to push through contentious Bills on the women's quota in Parliament and delimitation of parliamentary constituencies. Whatever be the outcome of these efforts, the point I wish to make is that these are major distractions from the important national issues of the day.We are today confronted with a situation where international crises are threatening our economy. We are being warned of gas shortages leading to the closure (full or partial) of industrial units ranging from chemicals, fertilisers, ceramics, glass and textiles to the humble restaurants. The effect of the spike in oil prices is already apparent in airfares and industrial diesel, with the country holding its breath on what will happen at the fuel pumps once the elections are done.Inflation is further creeping into most household items, with traders increasing prices as supply-side disruptions work their way into the system. Trading houses with large exposure to the Middle East are petitioning the government for relief. Our self-sufficiency in food itself is threatened by the large-scale disruption to fertiliser production and imports.

The Gulf countries are now an integral part of the global food economy. Adam Hanieh, Director of the SOAS (School of Oriental and African Studies) Middle East Institute, University of London, writes in the Financial Times: "They now shape the production and circulation of food directly, supply key chemical inputs, exporting large volumes of finished fertilisers and controlling the

logistical corridors through which food and agricultural commodities move across much of the Middle East, Central and East Asia, and Africa… Famine and widening food insecurity are the foreseeable consequences of military aggression in the Gulf. That reality ought to weigh heavily on a world that has largely understood this war through the narrow lens of oil price instability."Do remember that all this comes in the wake of a disruptive US tariff regime from which the industry is still recovering. The Indian crude basket's average price was $125 in March, hitting $150 at times due to the war in the Middle East. It is liable to stay elevated even if the ceasefire holds as Gulf nations have suffered major damage to their production and distribution infrastructure.In this scenario, inflation is almost a given, unless drastic measures are taken to develop new supply lines and restore some old ones (the Russian). This calls for a diplomatic resurgence on a war footing, failing which the future looks bleak. A surge in our energy prices invariably produces a chain reaction in prices of most other commodities and services as production and transport get greatly affected. The war-related disruptions are leading to unit closures, thereby increasing unemployment. This can be seen in the recent events in Noida, where disenchanted employees are protesting and getting violent. This is a situation which can be easily used and manipulated by forces inimical to us as our economy is threatened; added to this is a diplomatic morass that we find ourselves in.

The 1999 Kargil war was decisively won by India and the mountains were cleared of foreign belligerents. India also had tremendous diplomatic support and a parallel win in foreign affairs and diplomatic relations, which I wish to highlight: During the Cologne summit in June that year, G8 — the group of eight countries — condemned Pakistan's violation of the Line of Control (LoC) and expressed support for India. The European Union opposed the LoC violation and backed India's efforts to maintain territorial integrity. China maintained a neutral stance and urged both sides to respect the LoC.

Under then President Bill Clinton, the US took a firm stance against Pakistan and demanded the immediate and unconditional withdrawal of Pakistan's troops to its side of the LoC. Russia, India's long-standing ally, stood with it diplomatically and by providing military hardware. The point is that India received widespread support and Pakistan was gradually isolated and reduced almost to a sponsor of terrorism with various sanctions.

Today, it is a different world. When America wants to hold talks with Iran, it co-opts Pakistan and its Field Marshal. Iran also agrees and accepts them. They are wined and dined at the White House and suitably given a place at the high table. The Saudis have tied up with Pakistan in a mutual security and defence pact. Pakistan hosted the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit in October 2024 and continues to be a strategic hub for the Chinese Belt and Road Initiative (BRI) through the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).The Islamabad-Tehran-Istanbul rail link is also being revitalised; along with the BRI, it will lead to further integration of Pakistan with China, Turkey and Central Asian countries (we, on the other hand, have lost the Chabahar port, our potential link to Iran and Central Asia). Pakistan has re-established diplomatic relations with Bangladesh and is moving fast on economic and strategic fronts with them. The Pakistanis have also been given a seat on the UNSC as a non-permanent member.

Will petrol, diesel prices rise after elections? Here's what we know

The government has dismissed rumours of a petrol and diesel price hike, but elevated crude prices and pressure on oil retailers have kept the debate firmly alive.

New Delhi,.(Agency)

Fresh reports suggesting a possible petrol and diesel price hike after the ongoing elections have triggered concern among consumers, but the government has said no such proposal is currently under consideration.The speculation began after a report citing Kotak Institutional Equities said petrol and diesel prices may need to rise by Rs 25–28 per litre if global crude oil prices remain elevated and domestic retail fuel prices continue to stay unchanged.The estimate was linked to higher crude costs and the pressure on state-run oil marketing companies (OMCs) that sell fuel in the domestic market.The report quickly gained traction because petrol and diesel prices in India have remained largely unchanged for an extended period despite fluctuations in international crude oil markets.

However, the Ministry of Petroleum and Natural Gas has rejected claims of any imminent increase.In an official clarification, the ministry said there is no proposal under consideration by the government to raise petrol or diesel prices, and described such reports as misleading."There are some news reports suggesting a price hike of petrol and diesel. It is hereby clarified that there is no such proposal under consideration by the Government. Such news items are designed to create fear and panic amongst the citizens and are mischievous and misleading," the ministry said.

Following the ministry's clarification, it would be fair to say that no immediate increase in petrol and diesel prices appears likely after the elections.

While that comes as a relief for consumers, it also keeps the spotlight on state-run oil marketing companies, which may have to continue absorbing pressure if global crude prices remain above $100 per barrel.When crude oil prices rise internationally, but domestic pump prices stay unchanged, companies such as Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation Limited and Hindustan Petroleum Corporation Limited can see their marketing margins shrink, since part of the higher cost cannot be passed on immediately to consumers.Market analysts have also said the current pricing structure can be maintained in the short term if crude remains within a manageable range, but sustained high oil prices would increase pressure on company earnings and balance sheets.

There are signs consumers are watching closely. Recent media reports have indicated that fuel sales rose this month, suggesting some buyers may be filling tanks early amid fears of a possible hike.

For now, the government has drawn a line under hike rumours. Whether that holds will depend largely on where crude prices head next.

HCLTech, TCS, Infosys: Why are IT stocks falling again?

New Delhi,.(Agency)

Major information technology (IT) stocks came under fresh pressure on Friday, with heavyweight names such as HCLTech, TCS, Infosys and Tech Mahindra trading lower as investors turned cautious over global growth concerns, weak management commentary and renewed foreign fund selling.

At around 1:01 pm on the Bombay Stock Exchange (BSE), Infosys was down 6.20% at Rs 1,165.50, emerging as one of the biggest losers in the pack.HCLTech fell 5.70% to Rs 1,204.40, while TCS slipped 4.78% to Rs 2,402.05. Tech Mahindra was down 4.71% at Rs 1,353.55.The latest decline reflects a sector that is still struggling to regain investor confidence.

WHY IT STOCKS ARE UNDER PRESSURE

The biggest concern remains slowing demand in key overseas markets such as the US and Europe, where most Indian IT companies earn a large share of their revenue.When global companies become uncertain about growth, they often delay technology spending, reduce discretionary projects or renegotiate contracts.

That has a direct impact on Indian software exporters.

Recent earnings commentary from several IT majors has also done little to calm nerves. Management teams have spoken about cautious client behaviour, slower decision-making and an uneven recovery in deal conversion.While large contracts continue to come in, investors are worried that revenue growth may stay muted for longer than expected.

Another factor hurting sentiment is foreign investor activity. IT stocks are among the most widely owned sectors by overseas funds. When foreign portfolio investors trim exposure to emerging markets or move money into safer assets, frontline IT names often face selling pressure.

Businesses dole out up to $4 million to cross Panama Canal during Strait of Hormuz chokehold

PANAMA CITY.(Agency)

Businesses have doled out up as much as USD 4 million to move boats through the Panama Canal with the Strait of Hormuz effectively closed, according to the Panama Canal Authority, in a move that has created a seismic shift in global trade flows.

While passage through the waterway usually comes at a flat rate via reservations, companies without reservations can cross by paying an additional fee in an auction for slots, which are awarded to the highest bidder rather than waiting for days off the coast of Panama City.That price has ballooned in recent weeks as Iran and the United States have bottlenecked the key shipping route, the Strait of Hormuz, and demand for those slots has skyrocketed. Ships have increasingly travelled through the Panama Canal as shipments are rerouted and buyers purchase from other countries to avoid commerce through the now-treacherous West Asia waterway."With all the bombings, the missiles, the drones ... companies are saying it's safer and less expensive to cross through the Panama Canal," said Rodrigo Noriega, said lawyer and analyst in Panama City. "All of this is affecting global supply chains."

Meanwhile, Noriega said Panama's government is "maximizing what it can earn from the Panama Canal."The average price to cross through the canal ranges between USD 300,000 and USD 400,000 depending on the vessel. Previously, to get an earlier crossing, businesses would pay an additional USD 250,000 to USD 300,000. In recent weeks, the average additional cost has jumped to around USD 425,000.Ricaurte Vásquez, the canal's administrator, said another company that he would not name paid an extra USD 4 million when its fuel vessel had to change its destination because of ongoing geopolitical tensions."It was a ship carrying fuel to Europe, and they redirected it to Singapore, and it needed to get there because Singapore is running out of fuel," he said.

Rupee slips 24 paise to 94.25 against US dollar in early trade

New Delhi.(Agency)

The rupee stayed on a downward track for the fifth straight day, losing 24 paise to 94. 25 against the US dollar in early trade on Friday, weighed by volatile crude oil prices and an elevated US dollar, with prospects of West Asia peace talks turning hazier.

Analysts said that despite a ceasefire in place between the United States and Iran, ship movement through the Strait of Hormuz remained uncertain after the US military on Thursday seized another Iranian oil tanker, intensifying the standoff and unsettling the fuel prices worldwide.President Donald Trump has also ordered the US military to "shoot and kill" small Iranian boats that deploy mines to choke traffic through the Strait of Hormuz.Unabated withdrawal of foreign funds from domestic stock markets also added to investors' worries, triggering a massive sell-off in equities and further dragging down the local currency, forex traders said.At the interbank foreign exchange market, the rupee opened at 94.25 and stayed at the same level in early deals, registering a loss of 24 paise from the previous closing level.Extended its losing streak for the fourth consecutive session on Thursday, the rupee settled 23 paise lower at 94.01.In the past four sessions, the domestic unit has lost nearly 1.4 per cent, since the closing level of 92.91 recorded on April 17.Meanwhile, the dollar index, which gauges the greenback's strength against a basket of six currencies, was 0.12 per cent higher at 98.71.Brent crude, the global oil benchmark, was trading 0.86 per cent higher at USD 105.97 per barrel in futures trade.In the domestic equity markets the 30-share Sensex was trading 547.02 points or 0.70 per cent down at 77,116.98 in early trade, while the Nifty lost 159.75 points or 0.66 per cent to 24,013.30.

8th Pay Commission: Key meetings to begin in Delhi from April 28, more rounds planned

New Delhi.(Agency)

The 8th Pay Commission process is slowly picking up pace, with meetings set to begin in Delhi. At the same time, a widely discussed Rs 72,000 salary figure is creating confusion among central government employees.

MEETINGS TO BE HELD FROM APRIL 28 IN DELHI

In a notice dated April 24, 2026, the Commission said it has received a large number of requests from employee unions and associations for meetings scheduled between April 28 and April 30 in Delhi.Due to time constraints, not all requests can be accommodated during these dates. However, the Commission has assured that more meetings will be held in Delhi as well as in different states and Union Territories in the coming months.It also advised stakeholders outside Delhi-NCR to wait for future schedules when the Commission visits their respective states or nearby regions.

Earlier, as per a separate notice, a team of the Commission was scheduled to visit Dehradun, Uttarakhand, on April 24.

RS 72,000 FIGURE IS NOT AN OFFICIAL DEMAND

Amid these developments, a figure of Rs 72,000 as the expected minimum salary has been widely circulating online and in reports.In fact, the Rs 72,000 figure appears to be based on estimates and projections rather than any official submission.It is likely linked to different salary calculations under various fitment factor scenarios, which some analysts and reports have been discussing as possible outcomes.

Moreover, available records suggest that this is not an official demand submitted to the Commission.WHAT IS THE ACTUAL DEMAND?

The formal proposal comes from the National Council–Joint Consultative Machinery (NC-JCM), Staff Side, which represents central government employees.

According to its memorandum, the body has demanded a minimum basic pay of Rs 69,000 along with a fitment factor of 3.83.This proposal has been reported by several mainstream publications as part of the ongoing consultation process.WHAT SHOULD EMPLOYEES EXPECT NOW?

At this stage, the Pay Commission is in the consultation phase, where it gathers inputs from employee groups and stakeholders.Final recommendations on salaries, allowances and fitment factors will only come later, after detailed discussions and review.

For now, employees may need to wait for official updates rather than rely on circulating figures.

Infosys shares down 5%, hit 52-week low: Why IT stock tumbled after Q4 results

New Delhi.(Agency)

Shares of Infosys tumbled sharply on Friday, hitting a fresh 52-week low as investors reacted negatively to the company's subdued growth outlook and broader weakness across technology stocks.At around 11:01 am, Infosys shares were trading at Rs 1,178.20 on the NSE, down 5.03% or Rs 62.40 for the day. The fall made it one of the worst performers on benchmark indices as the IT pack remained under pressure.Infosys has projected 1.5% to 3.5% constant-currency revenue growth for FY27, lower than many analyst expectations, reinforcing concerns that demand recovery in the IT sector may take longer than hoped.While the company reported healthy March-quarter earnings, investors chose to focus on what lies ahead rather than what has already been delivered. In markets, forward guidance often matters more than backward-looking results.The cautious outlook comes at a time when global clients, especially in the US and Europe, remain careful about technology spending.Companies are still scrutinising budgets, delaying non-essential projects and taking longer to finalise contracts. That environment directly affects Indian IT exporters like Infosys, which derive a large portion of revenue from overseas markets.There is also growing concern about pricing pressure linked to artificial intelligence-led automation. Analysts have flagged that while AI opens fresh opportunities, it may also reduce billing rates for some traditional services and intensify competition in parts of the outsourcing market.Infosys was not alone in the sell-off. The broader IT pack also came under pressure, with peers such as Tata Consultancy Services, HCLTech and Tech Mahindra trading lower as sentiment toward the sector weakened.Adding to the pressure was a risk-off mood in the wider market. Rising crude oil prices, global geopolitical tensions and foreign investor selling have made investors more selective, often prompting them to cut exposure to sectors dependent on overseas demand.For long-term investors, the sharp fall raises the question of whether valuations are becoming attractive. But for now, the market seems more concerned about near-term growth visibility than bargain prices.Friday's drop shows the Street wants stronger evidence of recovery before turning positive on Infosys again. Until demand improves and guidance turns firmer, the stock may continue to face bouts of volatility.

Microsoft offers buyouts to staff: What does employee buyout mean?

HONG KONG.(Agency)

Microsoft will offer voluntary buyouts to some US employees, a first for the 51-year-old software giant, as the tech industry grapples with major changes sparked by the artificial intelligence boom.About 7% of US employees are eligible, reported CNBC. The one-time retirement program, announced in a memo on Thursday, will be available to US workers at the senior director level and below whose years of employment and age add up to 70 or higher.The move has brought attention to a term that many employees hear but may not fully understand — buyouts The development raises a broader question: what exactly is a buyout, and how does it affect employees?

WHAT IS AN EMPLOYEE BUYOUT

An employee buyout is a voluntary exit option offered by a company, where workers are given financial incentives to leave their jobs.Unlike layoffs, where employees are asked to leave, a buyout gives workers a choice. Companies usually offer:A lump sum payment

Extended benefits

Early retirement options

The idea is simple. Instead of forcing job cuts, companies try to reduce staff strength by encouraging employees to leave on their own terms.WHY COMPANIES OFFER BUYOUTS

Buyouts are often used when companies want to cut costs, restructure teams, or shift focus without resorting to layoffs.They are common during:Business slowdownsIndustry transitions

Organisational restructuring

In Microsoft's case, the move comes at a time when the tech industry is going through a major shift driven by artificial intelligence.The company is investing heavily in data centres and AI infrastructure, while also adjusting its workforce needs.

HOW MICROSOFT'S BUYOUT WILL WORK

Microsoft's programme will be available to US employees at the senior director level and below, whose age and years of service add up to 70 or more.Eligible employees and managers will receive details on May 7. However, those in sales roles with incentive-based pay will not be part of the programme.

AI security risk for banks? Why has Nirmala Sitharaman raised concerns

At the centre of the issue is Anthropic's new AI model, known as Claude Mythos Preview, capable of identifying and exploiting vulnerabilities across major operating systems and web browsers when prompted.

New Delhi,.(Agency)

A high-level meeting called by Finance Minister Nirmala Sitharaman with top bank officials on Thursday has brought a new concern into focus: whether rapidly advancing artificial intelligence tools could pose a risk to the country's banking system.The discussion centred around the potential cybersecurity threats linked to Anthropic's Claude Mythos model, a powerful AI system that has recently come under scrutiny after reports of unauthorised access.The development has added urgency to discussions within the government and financial sector, especially as banks increasingly rely on digital systems and AI tools.The company itself has described the model as highly advanced, capable of identifying and exploiting vulnerabilities across major operating systems and web browsers when prompted.

The model is not meant for public use. It is being tested in a controlled environment under a programme called Project Glasswing, with access limited to a handful of companies such as Nvidia, Google, Amazon Web Services, Apple and Microsoft.However, according to a Bloomberg report, a small group of users managed to gain access to the model through a third-party vendor environment on the same day it was introduced for limited testing.

Anthropic has confirmed that it is investigating the claim of unauthorised access."We're investigating a report claiming unauthorized access to Claude Mythos Preview through one of our third-party vendor environments," an Anthropic spokesperson said.WHY THIS MATTERS FOR BANKS

This incident has raised a key concern. If a restricted and highly powerful AI system can be accessed without permission, it raises the risk of misuse in sectors that rely heavily on digital infrastructure, including banking.

The Claude Mythos model is designed to detect security flaws. But in the wrong hands, such capabilities could potentially be used to exploit weaknesses in financial systems.This is where the government's concern comes in.Sitharaman's warning highlights the risk that AI tools could move from being a defence mechanism to a possible threat if not properly controlled.

WHY A MEETING WAS CALLED

The concern over such risks has led to discussions at the highest levels. The government is understood to be assessing how emerging AI tools could impact financial stability, cybersecurity, and data protection.The unauthorised access incident appears to have acted as a trigger, showing that even controlled AI deployments may not be fully secure.This has pushed regulators to take a closer look at how banks are using AI and what safeguards are in place.The issue is not just about one AI model. It reflects a broader shift in how powerful AI systems are becoming.As banks adopt AI for fraud detection, customer service, and operations, the same technology could be used to identify gaps in systems if misused.

This creates a new kind of risk where the threat is not just hackers, but advanced tools that can automate and scale attacks.

Heatwave May Melt 4% Of GDP, Raise Medical Bills, Dent Productivity

Extreme heat has already accounted for around $159 billion in lost productivity, roughly 5.4 per cent of India's income.

New Delhi.(Agency)

As the India Meteorological Department (IMD) issues widespread heatwave alerts across Haryana-Chandigarh-Delhi, Punjab, East Rajasthan, Bihar, Vidarbha (Maharashtra), Chhattisgarh and Jharkhand, economists and health experts are warning that the blistering heat will do more than sizzle temperatures -- it will squeeze economic growth, cut productivity and balloon medical costs. "Heatwaves in India are no longer just a health problem; they're a major economic crisis," says Dr Sujit Paul, Zota Healthcare Ltd. He points to analyses showing that extreme heat has already accounted for around $159 billion in lost productivity, roughly 5.4 per cent of India's income, with over 160 billion work hours lost annually because workers are unable to operate at peak output.

He adds, "By the end of the decade, heatwaves could hurt India's economy much more than anticipated, costing up to around 2.5-4.5 per cent of the country's GDP." Some estimates even suggest heat stress could cost India 8.7 per cent of GDP by mid-century without policy action.

Heat exposed sectors such as agriculture, construction and informal urban labour face the brunt. Outdoor workers, in particular, earn substantially less as they are forced to stop work during peak heat hours.

The Hidden Cost Of Heat

According to Dr Rashmi Ardey, Director Programme (Health), Smile Foundation, heat stress is now "imposing a substantial socio-economic burden through reduced labour productivity and income losses." She notes that a 1-degree Celsius rise in temperature can lower daily wages by around 16 per cent, and in severe conditions, earnings can fall by 40 per cent or more. That's a direct hit to millions of households that rely on daily wages.

Ardey's observations resonate with global estimates suggesting heat stress could reduce total working hours by 2-3 per cent by 2030. This would be a significant dent in a labour-intensive economy such as India's, where a large share of workers are employed outdoors.

Back in 2021-22, India lost an estimated 160-191 billion labour hours. This was equivalent to roughly 5.4-6.3 per cent of GDP -- translating into hundreds of billions of dollars in lost output. According to studies, informal workers are up to 17 times more likely to suffer productivity losses due to heat exposure.

Medical Bills Add Fuel To The Fire

Heat-related illnesses -- from dehydration and heat exhaustion to severe heatstroke - lead to a rise in medical expenditure during peak summers. Dr Nitin Jagasia, Regional Director Emergency Services, Western Region, Apollo Hospitals, underscores the financial shock: treatment of severe heatstroke can cost between Rs 1 lakh and Rs 2 lakh per patient, enough to wipe out a working family's savings.

2.5 yrs, 20 hearings and another extension: Delhi HC plea flags delay in DCPCR chairperson appointment

New Delhi.(Agency)

Nearly two years, over 20 hearings, and repeated rebukes from the Delhi High Court later, the city government continues to delay the appointment of a chairperson to the Delhi Commission for Protection of Child Rights – a post lying vacant since July 2023.

In its latest move, the government has sought yet another extension, drawing sharp criticism in court.

Following this, a fresh application was moved before the Delhi High Court on Thursday seeking an urgent hearing in a long-pending case concerning the functioning of the Delhi Commission for Protection of Child Rights (DCPCR), alleging continued delays by the Delhi government in appointing its Chairperson and members.

Filed by an advocate, the application flagged that despite repeated directions from the court, the process of filling vacancies in the statutory body remains incomplete. The matter, pending since 2018, is now currently listed for July 3, 2026, but the intervenor has urged the court to take it up earlier, citing its "urgent and crucial" nature involving children in need of care and protection.

The petition stemmed from compliance with directions issued by the Supreme Court of India in the landmark Sampurna Behura v. Union of India case, which mandates proper functioning of child protection mechanisms across states.

In its February 18, 2026 order, the HC had pulled up the GNCTD for its "lackadaisical approach" in operationalising the commission, noting that it had remained non-functional since July 2023. The court had expressed concern that such delays undermine key child welfare legislation, including the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, the Protection of Children from Sexual Offences Act, and the Commissions for Protection of Child Rights Act.

BJP, Congress file nominations for MCD mayor, deputy posts

New Delhi.(Agency)

The Bharatiya Janata Party and Indian National Congress on Thursday filed nominations for the posts of mayor, deputy mayor and members of the Standing Committee of the Municipal Corporation of Delhi, while the Aam Aadmi Party chose not to participate in the mayoral contest.

The BJP fielded Parvesh Wahi for mayor and Monika Pant for deputy mayor. Wahi, councillor from Ward No. 53 (Rohini-East) and former Leader of the House, filed his nomination on the last day, April 23. Pant, councillor from Ward No. 206 (Anand Vihar), also submitted her papers.

From the Congress, councillor Zarif (Ward No. 234) filed nomination for Mayor, while Rajesh Kumar Gupta (Ward No. 39) filed for Deputy Mayor. The AAP, however, did not field candidates for the two top posts, stating that it wanted to give the BJP "another opportunity" to govern Delhi and be held fully accountable.

For vacant Standing Committee seats, the BJP nominated Jai Bhagwan Yadav (Ward No. 27, Begampur) and Manish Chaddha (Ward No. 82), while AAP's Jalaj Kumar (Ward No. 55) filed nomination for one seat.

After filing his nomination, Wahi said clearing garbage and improving civic infrastructure would be top priorities.

The elections for Mayor and Deputy Mayor will be held during the MCD House meeting scheduled on April 29. The electoral college comprises 273 voters, and a candidate requires 137 votes to win.

AAP's Ankush Narang reappointed LoP in civic body

The AAP has reappointed Ankush Narang as Leader of Opposition in the Municipal Corporation of Delhi. Narang said the role reflects people's trust and pledged to raise civic issues with dedication. He claimed the House functioned smoothly over the past year with AAP in opposition, unlike earlier disruptions. He said the party raised concerns over monsoon preparedness, waterlogging, pollution and vector-borne diseases. Narang alleged the BJP failed to deliver in the MCD.

'Enticement, Intimidation By Trinamool': Adhir Chowdhury On Women's Turnout

New Delhi.(Agency)

91 lakh voters deleted from its electoral rolls, West Bengal recorded a 91 per cent turnout in the first phase of Assembly polls today. But more than the overall turnout, it is the presence of women that's key to this election, veteran Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury indicated today.

Women have always been the core supporters of Chief Minister Mamata Banerjee. But their overwhelming presence at the hustings has been interpreted positively this time by both Trinamool Congress and the BJP.

While Trinamool leaders said they were there show support for the party, the BJP declared that it was their anger that they had come to project through the ballot box following events like the RG Kar rape case and the Sandeshkhali sex abuse.

"The Trinamool has both enticed and intimidated female voters, warning them that if they did not vote for the party, the 'Lakshmir Bhandar' scheme would be discontinued," said Adhir Ranjan Chowdhury

In an exclusive interview with , Adhir Chowdhury gave a completely different spin to the matter.

"The Trinamool has both enticed and intimidated female voters, warning them that if they did not vote for the party, the 'Lakshmir Bhandar' scheme would be discontinued," said the 70-year-old.

He, however, added that a high voter turnout among women is, "in itself, a very positive development for our society".Asked if the 'Lakshmir Bhandar' scheme -- a financial assistance scheme for the poor -- has had an impact, he answered in the affirmative.There is the "fear that if Mamata Banerjee does not return to power, the scheme will be shut down," he said.

When pointed out that the BJP also promised a scheme that would provide more financial assistance, he said there is a fundamental difference between a party that is currently providing money and another that is just promising to do so in future.

Delhi begins online regularisation of unauthorised colonies from April 24

New Delhi.(Agency)

The process for regularisation of properties in unauthorised colonies in Delhi will begin from April 24, allowing residents to apply online through the SWAGAM portal of the Municipal Corporation of Delhi (MCD), officials said. The move follows the Centre's rollout of a new policy earlier this month to regularise such colonies on an "as is where is" basis.

According to officials, property owners in 1,521 identified unauthorised colonies can log on to the SWAGAM portal to apply for registration. Applicants who already possess conveyance deeds (for properties on government land) or authorisation slips (for properties on private land), earlier issued by the Delhi Development Authority (DDA), can directly apply for regularisation.

Those lacking these documents will be redirected to the PM-UDAY portal to obtain them before proceeding further.

Under the revised framework, the authority to issue conveyance deeds and authorisation slips has been transferred from the DDA to the Revenue Department of the Delhi government. Dedicated cells under Additional District Magistrates (ADMs) are being set up in all 13 districts, with ADMs acting as nodal officers.

The initiative is expected to benefit over 10 lakh households. Once documents are issued, the MCD will grant regularisation certificates via the SWAGAM portal. Officials said the entire process will be conducted online through an integrated digital system.

Delhi murder accused scored 90% in Class 12, pawned marksheet for betting

Once a promising student, Rahul Meena's descent into online gambling and mounting debt culminated in the brutal murder of the IRS officer in Delhi.

New Delhi.(Agency)

A year ago, when 26 civilians were brutally killed in Pahalgam's Baisaran Valley, the Pakistani terrorists who carried out the massacre emerged from the tree line of the meadow. Baisaran, located above Pahalgam town, is surrounded by forested slopes. Imagine it as a hidden bowl in the mountains, among the most treacherous in India. This mountain range, called the Pir Panjal range, shapes the mountain zone close to Baisaran Valley. Pir Panjal has a history, quite a long one, when it comes to terrorism. Back in the 2000s, when it was not fenced, it allowed cross-border terrorismnd deodar, form a canopy stretching for kilometres across the Line of Control (LoC), making it difficult for surveillance drones to do their job efficiently. However, there are also stretches of open, rocky ground, along with terrain that remains snow-covered for much of the year.

This is terrain where there is heavy deployment of the Indian Army, and where special forces units operate in full force. A serving Lt Colonel says ambushes are set up in these forests depending on intelligence that comes from the ground.

The family said Meena's father had previously worked in Delhi, including in houses of Income Tax officers. Through these contacts, Meena later secured work at the home of the IRS officer whose daughter was killed. He had been employed there for about eight months and was familiar with the house layout.

Police said his gambling continued during his time in Delhi, with Meena allegedly losing large sums and borrowing money from shopkeepers and locals. He is also accused of cheating the family while running errands, including taking money for medicines but failing to pay shopkeepers and instead purchasing items on credit. After complaints about his conduct reached the officer's family, he was dismissed from the job.Meena returned to his village around one-and-a-half months ago, telling his family he was on leave and had arranged a replacement. Even then, he continued gambling online. His family claimed that days before the Delhi incident, he had won Rs 5 lakh, after which friends encouraged him to play using their accounts.

IRS officer's daughter's killer showed psychopathic traits with violent past: Probe

A 23-year-old accused in the IRS officer's daughter murder case has been described as psychopathic, with a history of violence and a gambling addiction, investigators said.

New Delhi.(Agency)

Investigators in the Delhi IRS officer's daughter murder case have described the accused, 23-year-old Rahul Meena, as having psychopathic tendencies and a history of violent behaviour, according to sources. They said Meena was already infamous in his village for his aggression and addicted to Teen Patti card games and also used to bet on other apps as well.

Delhi Police have recovered more than Rs 1 lakh in cash and stolen jewellery from Meena. The recovery was made from a hotel room in Dwarka, where he had been staying after the crime. Police said he paid the hotel rent using money stolen from the victim's house. During interrogation, Meena admitted to two rape cases so far. Investigators are also identifying people who had lent him money, as he was addicted to online betting and frequently borrowed funds to gamble.

2 RAPES WITHIN 12 HOURS

The case involves a chilling sequence of crimes committed within a span of less than 12 hours. On Tuesday night around 10:30 pm, Meena allegedly entered a neighbour's house in Rajasthan's Alwar, assaulted her, and raped her. He allegedly strangled and threatened her before fleeing around 11 pm, warning her against reporting the crime. An FIR was later registered based on the survivor's complaint.

The next morning, Meena travelled nearly 200 km to Delhi and entered a residential society in south-east Delhi's Kailash Hills at around 6:30 am. He proceeded to the flat of his former employer, an IRS officer, where he had worked as a house help until a few months ago.

Police said Meena used his familiarity with the house layout, access codes, and spare key locations to enter the flat. He went to the rooftop study room, where the 22-year-old victim, an engineering graduate and UPSC aspirant, was studying. He allegedly attacked her with a lamp and a heavy object, causing severe injuries. When she resisted, he strangled her until she lost consciousness.

NEWS BOX

Iran hits back at Trump's 'hellhole' remark on India, China; calls them 'cradles of civilisation'

World. (Agency)

Iran has come down heavily on US President Donald Trump for sharing a video calling India and China "hellholes" amid the birthright citizenship debate in

In a post on X, Iran's Consulate General in Hyderabad defended India and China as historic civilisations.

"China and India are the cradles of Civilization. In fact, the hellhole is where its war-criminal president threatened to decimate the civilization in Iran," the post read.Similarly, Iran's Consulate General in Mumbai shared a video on Maharashtra's cultural and geographical heritage, and said Trump should visit the state for a "cultural detox". The post added, "Kabhi India aa ke dekho, phir bolna".

The reactions came after Trump shared a video featuring conservative author and radio host Michael Savage, in which Savage sharply criticizes the concept of birthright citizenship.In the podcast, Savage' referred to India, China and some other countries as "hell-holes" and called for changes in the US' birthright citizenship law. He also termed Indian and Chinese immigrants as "gangsters with laptops" who have "stepped on our flag.The clip, originally broadcast on Savage's Newsmax program The Savage Nation, was reposted by a Truth Social account that amplifies the president's online activity. In the video, Savage argues that current interpretations of birthright citizenship laws allow immigrants to exploit the system by entering the United States late in pregnancy so their children are born as citizens.

In the clip, Savage claimed that the practice creates a loophole in which a child born in the United States automatically gains citizenship, after which extended family members can later immigrate. He referred to India, China and other nations as "hell-holes" from where people bring their entire family to the US.

Ukraine's Remote-Controlled Drones Can Hit Targets At Great Distance, Says Minister

Kyiv.(Agency)

Ukraine has developed interceptor drones that can be directed from a distance and are capable of hitting targets hundreds or thousands of kilometres away, Defence Minister Mykhailo Fedorov said on Thursday.Ukraine was virtually without any capacity to build drones when Russia launched its full-scale invasion in 2022, but now has a thriving industry.

Emphasis has been placed on interceptor drones as a more effective - and more economical - means to defend against drone attacks."We are launching a new level of 'small' air defence. Now, control of interceptors is possible at a distance of thousands of kilometres," Fedorov wrote on the Telegram messaging app."Today we have a confirmed result -- downing a target at a distance of hundreds and thousands of kilometres. Ukraine is the first in the world to systematically scale remote control of interceptor drones."Fedorov said the system "increases the efficiency of interception, minimises risks for operators and allows scaling capabilities without being tied to the front line".Ukrainian officials estimated domestic drone production last year at about 4.5 million and capacity has since increased.Ukraine still faces large barrages of Russian drone and missile attacks more than four years into its war with Russia.In this year's largest attack last week, in which 17 people died, Ukraine said its air force units had shot down or neutralised 31 missiles and 636 drones, but 12 missiles and 20 drones struck targets.

Ukraine has established joint arms production with several European countries, and Kyiv has offered help to Middle East countries countering Iranian drones, concluding accords with Saudi Arabia, Qatar and the United Arab Emirates.

Massive Ice Chunk Blocks Mount Everest Route As Climbing Season Begins

WASHINGTON.(Agency)

A massive and unstable block of glacier ice has disrupted the main climbing route to Mount Everest from Base Camp in Nepal. Serac, a towering 100-foot-high chunk of ice, is preventing teams from moving beyond a key section of the route near Camp 1, BBC reported.The obstruction came close on the heels of a busy spring climbing season getting underway.Specialist Sherpa teams, commonly referred to as "icefall doctors," are responsible for setting up ropes and ladders along the dangerous Khumbu Icefall section of the climb. But they have been unable to find a safe path around serac.

With no viable alternative route, the teams say they have no option but to wait for the ice to naturally melt or collapse.This delay has already pushed back preparations by several weeks. Typically, by this time in April, route-fixing work would have progressed as far as Camp 3. But this year, teams remain stuck nearly 600 metres below Camp 1 due to the obstruction.The icefall doctors are employed by the Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC), which is tasked with preparing and securing the climbing route up to Camp 2. The team arrived at Base Camp about three weeks ago but has since been unable to advance further.SPCC base camp coordinator Tshering Tenzing Sherpa said that attempts to deal with the blockage have not been successful so far. "We haven't found artificial ways to melt it so far, so we don't have any options other than to wait for it to melt and crumble itself," he told the BBC.Ang Sarki Sherpa, who has years of experience working as an icefall doctor, said there are signs that the base of the ice block is getting weaker. He explained that crevasse beneath the serac is already melting and that it could collapse soon.Despite assessing multiple possible paths, teams have concluded that climbing over or around the ice structure would be too dangerous.

Why the European Union's wartime loan is a vital lifeline for cash-strapped Ukraine

Approval had been held up for months amid political friction inside the 27-nation EU, including resistance from outgoing Hungarian PM Viktor Orbán, widely seen as Russia's closest ally in the bloc.

KYIV. (Agency)

Cash-strapped Ukraine has secured a crucial European Union loan that will provide a vital lifeline to sustain its wartime efforts this year.The 90 billion-euro ($106 billion) package was formally approved on Thursday, days after Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy announced that the Ukrainian section of the Druzhba pipeline had been repaired and the flow of oil would resume to Slovakia and Hungary, conditions linked to the release of the funds.

Approval had been held up for months amid political friction inside the 27-nation EU, including resistance from outgoing Hungarian Prime Minister Viktor Orbán, widely seen as the Kremlin's closest ally in the bloc. Orbán was defeated in an election earlier this month, clearing the way for a breakthrough in negotiations.

Here's the importance of the EU package:

Why Kyiv needs the loanThe funding arrives at a critical moment. The International Monetary Fund estimates that Ukraine faces a financing gap of roughly 136 billion euros ($158 billion) over the next two years.

The EU loan is expected to cover about two-thirds of Ukraine's funding needs in 2026 and 2027. Without it, officials warn that Kyiv could have run out of resources to sustain basic state functions and its war effort as early as this spring. The first

tranche of funding is expected to be released in the coming months.Ukraine will have access to 45 billion euros ($53 billion) for the remainder of this year, and 45 billion euros ($53 billion) for all of 2027.Under the agreement, roughly a third of the funds will go toward budgetary support for Ukraine's government, while the remainder will be directed to defense, covering weapons procurement and expanding domestic arms production.Why it took so longEU leaders agreed to the loan in December 2025, but implementation stalled for months amid a dispute over the Ukraine-linked section of the Druzhba oil pipeline.In December, the Czech Republic, Hungary and Slovakia agreed not to stop their EU partners from borrowing the money on international markets as long as the three countries didn't have to take part.

The pipeline, which carries Russian oil to Slovakia and Hungary, went offline in late January after Ukrainian officials said it was damaged in a Russian attack. The Hungarian and Slovakian governments accused Ukraine of deliberately cutting off supplies, turning the issue into a broader political standoff inside the EU.The loan was finally unblocked after Hungary and Slovakia said that Ukraine had restored transit this week. Zelenskyy said that repairs had been completed, removing the final obstacle to approval.

Pakistan military kills 22 militants in northwest clashes, child dead in

A ten-year-old child was killed during the exchange of fire, which took place in Khyber district near the border with Afghanistan.

PESHAWAR.(Agency)

Pakistani security personnel shot dead 22 alleged militants in clashes in the northwest this week, the military said on Friday, with a child also killed in the crossfire.On Tuesday "a joint military operation was conducted by security forces and law enforcement agencies" that resulted in "intense exchange of fire" in which the militants were killed, a military media wing statement said.

A ten-year-old child was killed during the exchange of fire, which took place in Khyber district near the border with Afghanistan.Prime Minister Shehbaz

Sharif "expressed sorrow at the martyrdom of a 10-year-old child in the unprovoked firing by the terrorists", according to a statement from his office.Attacks, many claimed by the Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) armed group, have escalated in recent years, especially in the provinces bordering Afghanistan.

Pakistan has accused Afghanistan of providing a safe haven to militants since the Afghan Taliban returned to governing the country in 2021, which Kabul has repeatedly denied.

The assertions have frayed the relationship between the neighbours and led to regular border clashes.

Pakistan's military this year launched a wave of strikes the defence minister called "open war" in Afghanistan following a string of deadly suicide bombings.

Exchange of gunfire inside Mall of Louisiana leaves one person dead, 5 wounded

The shooting began around 1:30 p.m. when the two groups argued inside the food court and started shooting at each other, Police Chief TJ Morse said.

BATON ROUGE.(Agency)

An exchange of gunfire at a food court inside a Louisiana mall on Thursday killed one person and wounded five others and sent workers and shoppers scrambling for safety, police and witnesses said.Authorities described the shooting inside the Mall of Louisiana in Baton Rouge as a confrontation between two groups of people and not a random attack. Louisiana Attorney General Liz Murrill said some innocent bystanders were struck by gunfire.Police Chief TJ Morse said five people were in custody and there was no ongoing threat to the public.

Three high school seniors from Ascension Episcopal School were among the victims of the shooting, according to a Facebook post from Lafayette Parish President Monique Blanco Boulet.We are heartbroken by the senseless violence that happened today at the Mall of Louisiana in Baton Rouge," she said, adding that

she was asking her community to "join us in holding all of these families close in prayer."

Rachel Delcambre, a spokesperson for the school, said in an email that the school would not be giving additional information at this time "out of deep respect for the families and the sensitivity of this situation."

Authorities initially said as many as 10 people had been injured but later revised that number. Morse did not immediately say what set off the shooting at the mall in the Louisiana capital.Alex Theriot, a commercial electrician, was working on a construction project in the mall a few hundred feet from the food court when gunfire erupted and he heard what sounded like plates of glass shattering. Thinking a shooter might be going store to store, he quickly screwed the door shut of his work site and hunkered down with two other workers. They waited and hoped for the best."Everybody was running and screaming," Theriot told The Associated Press. "I thought it could have been a terrorist attack."

Desire Batton, who works at a clothing store, said she and other workers dashed inside a breakroom to protect themselves.

"We hid in there until cops came and got us," Batton said.The shooting began around 1:30 p.m. when the two groups argued inside the food court and started shooting at each other, Morse said. The chief made public appeals for witnesses to come forward with any video of the shooting.

Over 1.2 million travelled from region as India issues fresh Iran advisory

DALLAS.(Agency)

The Indian Embassy in Iran has issued a renewed advisory urging Indian nationals to avoid travelling to the country amid ongoing regional tensions and continued disruptions to international flight operations.In a post on X, the mission strongly cautioned citizens against visiting Iran "by any mode," citing persistent airspace restrictions and operational uncertainties affecting flights to and from the country. The Embassy also advised Indians currently in Iran to leave at the earliest, but only in close coordination with officials.

"Indian citizens are strongly advised not to travel to Iran, whether by air or land. Airspace restrictions and operational uncertainties due to regional tensions

continue to affect international flight operations," the statement said.The Embassy further emphasized that those already in Iran should exit through designated land border routes, strictly under its guidance. It warned against independently approaching border crossings without prior consultation. Emergency contact numbers and a consular email have been provided to assist citizens in coordinating their departure.This advisory follows an earlier notice issued on April 8, which similarly urged Indian nationals to leave Iran "expeditiously" in view of evolving regional developments. Officials have reiterated that all exits must be planned and executed in consultation with the mission to ensure safety.Meanwhile, speaking at an inter-ministerial briefing on developments in West Asia, Aseem R Mahajan, Additional Secretary (Gulf) at the Ministry of External Affairs, said that flight operations in the region are gradually stabilising despite ongoing challenges.He noted that since February 28, approximately 1.21 million passengers have travelled from the region to India.

Pope urges US and Iran to return to peace talks, condemns capital punishment

ABOARD THE PAPAL PLANE.(Agency)

Pope Leo XIV urged the United States and Iran to return to talks to end the war Thursday and condemned capital punishment, in a wide-ranging press conference en route home from his trip to Africa.Leo also asserted that countries have the right to control their borders but mustn't treat migrants worse than "animals," and lamented that the church's morality teaching is often reduced to sexual issues.

On Iran, capital punishment and peace

After a trip that was dominated by the very public back and forth between Leo and US President Donald Trump over the war, Leo urged the United States and Iran to return to negotiations.He called for a new "culture of peace" to replace the recourse to violence whenever conflicts arise.He said the question wasn't whether the Iran regime should change or not. "The question should be about how to promote the values we believe in without the deaths of so many innocents."He revealed that he carries with him the photo of a Muslim Lebanese boy who had been killed in Israel's recent war with Hezbollah. The boy had been photographed holding a sign welcoming the pope when he visited Lebanon last year.

"As a pastor I cannot be in favor of war," he told reporters aboard his plane. "I would like to encourage everyone to find responses that come from a culture of peace and not hatred and division."

Asked if he condemned Iran's recent executions, Leo said he condemned "all actions that are unjust" and included capital punishment in the list.

"I condemn the taking of people's lives. I condemn capital punishment. I believe human life is to be respected and that all people from conception to natural (death), their lives should be respected and protected."So when a regime, when a country takes decisions which take away the lives of other people unjustly, then obviously that is something that should be condemned," he said.Pope Francis changed the church's social teaching to declare capital punishment immoral in all cases.

On migration and the rights of states

Leo affirmed the right of countries to impose immigration controls on their borders and acknowledged that uncontrolled migration had created situations "that are sometimes

more unjust in the place where they arrive than from where they left.""I personally believe that a state has the right to impose rules for its frontiers," he said. "But saying this, I ask: 'What are we doing in the wealthier countries to change the situation in poorer countries' to provide opportunities so that people aren't compelled to leave?"Regardless, he said migrants are human beings and deserve to be respected in their human dignity and not be treated "worse than house pets, animals."

On LGBTQ+ blessings and morality

Leo was asked about the recent invitation by Cardinal Reinhard Marx, archbishop of Munich, for the priests and pastoral workers in his archdioceses to adopt a set of guidelines formalizing and ritualizing blessings of same-sex couples.

The guidelines were approved last year by a controversial German church governing body made up of the German bishops' conference and a Catholic lay group that has been working to have a greater say in church decision-making.The Vatican in 2023 allowed for such blessings, but it made clear that they were not to be formalized or ritualized.

NEWS BOX

A poem for Sanju Samson: Shashi Tharoor celebrates CSK star's century vs MI in verse

Mumbai. (Agency)

After Chennai Super Kings' clinical victory over the Mumbai Indians at the Wankhede Stadium on Thursday, the most resonant tribute to Sanju Samson's match-winning century came not from the commentary box, but from the literary world. Shashi Tharoor, Member of Parliament and a long-standing advocate for the Kerala-born wicketkeeper-batter, took to social media to celebrate the milestone with a specially composed poem.The tribute was crafted in a classic lyric style, utilising AABB rhyming couplets to mirror the rhythmic, balanced nature of Samson's batting. The structure-where the first line rhymes with the second, and the third with the fourth – provides a melodic pace that reflects the effortless flight Tharoor describes in his verses.It was Samson's second century for CSK in IPL 2026 as the new wicketkeeper-batter, traded from Rajasthan Royals, has made an instant impact for the Super Kings. He became only the second CSK batter after Shane Watson in 2018 to hit two hundreds in an IPL season.The poem is certainly an ode to the technical purity that has defined Samson's 2026 season, particularly his ability to maintain stylish command without resorting to slogging.

Sanju Samson's unbeaten 101 off 54 balls was the cornerstone of Chennai Super Kings' authoritative performance against the Mumbai Indians. Entering the fray early, Samson anchored the innings with a blend of traditional stroke-play and modern power-hitting, striking 10 boundaries and six maximums to propel CSK to a formidable total.It was Samson's game awareness that stood out. Taking on the onus of batting through 20 overs, Samson held one end even when wickets were falling at the other. In the death overs, Samson ensured he did not take risks against Jasprit Bumrah, Mumbai Indians' lead pacer and went after rookie Krish Bhagat in the last over, plundering 15 runs and pushing the total beyond 200.Despite the hosts' attempt to bolster their line-up with a controversial concussion substitute, they were blindsided by CSK's tactical masterstroke: the introduction of Akeal Hosein as an Impact Player.

Concussion Sub for shoulder injury? MI explain debatable Mitchell Santner call

NEW DELHI. (Agency)

Mumbai Indians' decision to replace Mitchell Santner with Shardul Thakur under the concussion substitute rule sparked debate after their defeat to Chennai Super Kings at the Wankhede Stadium on Thursday. The change was approved by match officials during the second innings after Santner suffered a fall while fielding late in the CSK innings. MI vs CSK: HIGHLIGHTS | SCORECARD

The point of dispute was not only the medical basis for the substitution, but also whether Thakur met the requirement of being a like-for-like replacement for Santner.The flashpoint occurred in the 17th over when Santner completed a diving catch to dismiss Kartik Sharma. While the New Zealand international was immediately seen clutching his left shoulder and subsequently received treatment in the dugout with an ice pack and a sling, the formal request for a substitute was made on the grounds of a suspected concussion.Under IPL playing

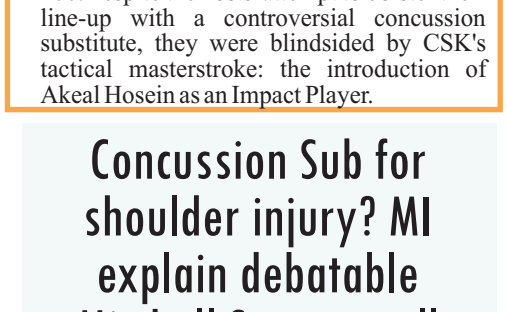

conditions, a concussion substitute is allowed if a player has suffered a head or neck injury, provided the Match Referee is satisfied with the medical diagnosis. The debate arose because the visible injury appeared to be to Santner's shoulder, while the substitute request was made on the basis of neurological symptoms.

MI COACH DEFENDS CONCUSSION SUB CALL

Speaking after the match, Mumbai Indians head coach Mahela Jayawardene explained the team's medical position."He hit his head first and neck. Obviously, the shoulder as well," Jayawardene said."He went for a scan. Once he got back, he felt dizziness. So, he was lying down. Yes, the ice was there for the shoulder. But, he felt he wasn't stable. So, we took him for a scan."The choice of Thakur as the replacement also came under scrutiny because Santner is a left-arm orthodox spinner, while Thakur is a right-arm medium-pacer.Jayaward

BCB revokes Mustafizur Rahman's NOC for PSL 2026 after medical assessment

In an official statement, the BCB confirmed that Mustafizur will undergo an immediate scan to determine the extent of his condition.

NEW DELHI. (Agency)

The Bangladesh Cricket Board (BCB) has revoked the No Objection Certificate (NOC) granted to pacer Mustafizur Rahman for Pakistan Super League 2026 after a medical assessment following the third ODI against New Zealand.In an official statement, the BCB confirmed that Mustafizur will undergo an immediate scan to determine the extent of his condition.He will then begin a rehabilitation programme under the supervision of the board's medical team, ruling him out for the rest of the ongoing PSL season.

"The Bangladesh Cricket Board (BCB) wishes to inform that, following the conclusion of the 3rd ODI against New Zealand, the team's medical staff has reviewed the condition of national team pace bowler Mustafizur Rahman," the BCB said on Thursday in a statement.

"It has been decided that the player will undergo an immediate scan to further assess his condition, after which he will commence a rehabilitation programme under the supervision of the BCB Medical Team."In this regard, the Board has withdrawn the No Objection Certificate (NOC) previously issued to Mustafizur. He will therefore not be available to participate in the remainder of PSL 2026," it added.

Mustafizur, who was forced to exit the IPL 2026 season after the BCCI directed the Kolkata Knight Riders to release him from their squad, was playing for Lahore Qalandars and had taken six wickets in five matches this PSL season.In a separate decision, the BCB confirmed that fellow fast bowler Nahid Rana will not be released for PSL 2026.The move is aimed at allowing the young pacer adequate time to prepare for Bangladesh's upcoming Test series against Pakistan next month.The decisions underline the board's focus on player fitness and national commitments ahead of a busy international schedule.Bangladesh won the third ODI against New Zealand by 55 runs, clinching the series 2-1 on Thursday.

IPL 2026: Called it? Akeal Hosein's Jadeja-like performance resurfaces old tweet

IPL 2026: Akeal Hosein's four-wicket haul for CSK against MI at the Wankhede brought back an old tweet where he had expressed admiration for Ravindra Jadeja, drawing striking comparisons. His powerplay impact and all-round consistency once again underlined his abilities as a match-winner.

Mumbai.(Agency)

Back in 2013, when a boy from Trinidad and Tobago made public his admiration for India's legendary all-rounder Ravindra Jadeja, hardly anyone noticed. But when Akeal Hosein bagged a four-wicket haul for Chennai Super Kings at the iconic Wankhede against fellow five-time champions Mumbai Indians, that 13-year-old manifestation resurfacedBack then, Hosein was just a 20-year-old, yet to make his List A or T20 debut, letting the world know about his role model via a tweet. Although Hosein has produced starring performances against India, his display against MI on Thursday night is what truly brought the resemblance out. The West Indian spinner was bought by CSK for Rs 2 crore during the 2026 IPL Auction.A left-arm orthodox spinner himself, Akeal struck gold in the very first over, getting the better of rookie batter Danish Malewar and sending him back for a golden duck. The impact substitute, Hosein then dismissed in-form Naman Dhir, ending with a wicket-maiden over.He later returned in the middle overs to wrap up MI's chase by removing Tilak Varma and Suryakumar Yadav. The West Indian finished with figures of 4-17, a performance

truly replicating the impact Jadeja had during his time with the yellow jersey.

"I think one thing that sticks with me is what Dwayne Bravo said. He said as bowlers, and as spinners and guys who operate in the powerplay, you're going to get hit. So as long as you can get that out of your mind and just focus on your plans—what are the batter's strengths and weaknesses, and what are your strengths and weaknesses—and as long as you focus on what you're going to execute and forget about being scared of getting hit, I think you're fine," Hosein said about his game after the match against MI.And social media was quick to bring that old tweet back, with users agreeing that he had indeed done what Jadeja used to do.However, this was not the first time Hosein had pulled off a moment of brilliance. In a T20I against England in January 2022, Hosein hit a hat-trick of sixes and two fours in the last over and nearly won West Indies the match when they needed 30 runs off six balls. West Indies fell one run short of the target. Then in 2023, against India in a T20I, he delivered an all-round performance, picking up two important wickets while scoring a match-winning 16 off 10 balls to take West Indies over the line.

Patidar has stuck to team's line of thinking: Mo Bobat on RCB's aggressive cricket

Bengaluru. (Agency)

Royal Challengers Bengaluru director of cricket Mo Bobat has underlined the team's commitment to maintaining its aggressive brand of cricket ahead of their clash against Gujarat Titans in the Indian Premier League, while also praising skipper Rajat Patidar for fully embracing the philosophy.RCB have played with an ultra-aggressive mindset in the tournament so far, refusing to take their foot off the pedal even when they have lost wickets in clusters."I want us to play aggressive cricket. I want us to be brave—brave when those moments really require bravery. When the game is on the line or things get a little bit difficult, if we're aggressive and brave through every phase, I think we'll play the way we want to play," said Bobat on the eve of the game against Gujarat Titans, as quoted by PTI.Under Patidar's leadership, RCB secured their maiden IPL title last year and have started strongly this season as well, winning four of their six matches to sit third on the table.

"We plan with aggressive tactics as our preference. But Rajat has to make his own decisions out there, and he's very good at that. One of Rajat's biggest strengths is that he's incredibly calm," Bobat added.Bobat believes Patidar has stuck to the team's line of thinking while still making bold decisions on the field. "When it gets a little bit chaotic, he's quite good at just remaining calm and sticking to the things that he thought he wanted to do. With the bat, that means he's quite good at leading from the front. In the field, he's always trying to take wickets, which is great. That is part of our identity and the way we want to play, and he's a good fit for that," he continued.."

Mumbai's El Clasico nightmare, Chennai's delight at Wankhede: In Stats

New Delhi. (Agency)

Chennai Super Kings produced a dominant display on April 23 at the Wankhede Stadium, defeating Mumbai Indians by 103 runs in IPL 2026 El Clasico. With the win in one of the tournament's marquee clashes, CSK, who had started the season with three losses on the trot, moved up to fifth in the table.Asked to bat first, CSK posted a commanding 207, powered by a superb unbeaten century from Sanju Samson. He anchored the innings from start to finish, ensuring stability through the middle overs before accelerating in the death phase to give CSK a strong finish.In reply, MI never recovered from early setbacks and were

bowled out for 104 in 19 overs. The turning point came through CSK's spin attack, led by Akeal Hosein, who delivered a four-wicket haul to dismantle the batting line-up. Noor Ahmad also played a key supporting role with two wickets. MI kept losing wickets in clusters and failed to build any significant partnerships.Suryakumar Yadav and Tilak Varma showed brief resistance, but the required rate kept spiralling as CSK's bowlers maintained relentless pressure with disciplined lines, clever variations, and effective use of slower deliveries on a gripping Wankhede surface.After the win, CSK return to Chepauk, where they will face Gujarat Titans on April 26. MI, on the other hand, will look to bounce back when they take on Sunrisers Hyderabad on April 29 at the Wankhede Stadium.The win was CSK's biggest margin of victory by runs in IPL history. It was also the first time they had won an IPL match by 100 or more runs.

RCB vs GT Preview: RCB look to reclaim fortress Chinnaswamy, prey on wounded Gujarat Titans

IPL 2026: The Gujarat Titans face Royal Challengers Bengaluru at the M. Chinnaswamy Stadium in a high-stakes clash between Shubman Gill's side with struggling middle order and Rajat Patidar's side with vulnerable death bowling. With the head-to-head record at this venue favoring the Titans, both teams are seeking a crucial batting resurgence in their final home league game of the season.

NEW DELHI. (Agency)

It is the ultimate "King vs. Prince" narrative as Virat Kohli's Royal Challengers Bengaluru (RCB) prepare to host Shubman Gill's Gujarat Titans (GT) at the M. Chinnaswamy Stadium. With both teams seeking a vital win, the "Prince" will be looking to rally his wounded Titans and breach the "King's" fortress in what promises to be a high-octane encounter.Despite their recent struggles, the Titans will look to remain confident. However, form is not currently on their side. GT enters this fixture reeling from a crushing 99-run defeat against the Mumbai Indians, a loss that exposed significant cracks in their lower middle order.RCB, on the other hand, find themselves in a slightly better position on the table, having won four of their last six matches. Nevertheless, they also come into this game following a frustrating home defeat to the Delhi Capitals. In that match, victory slipped through their fingers in the final over when David Miller's clinical counterattack against Romario Shepherd halted RCB's momentum.However, more than batting, it might prove to be a battle of bowlers when the likes of Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, and Prasidh Krishna take on

Bhuvneshwar Kumar, Josh Hazlewood, and possibly Rasikh Salam Dhar. If there's any zip or movement in the pitch, it could be a riveting contest, with elite operators either hitting top gear or using subtle variation to outthink some of the game's best batters. Meanwhile, Krunal Pandya and Rashid Khan might try to turn and bounce things in their teams' favour during the middle over phase.

As this will be the final league game of the season at the Chinnaswamy, RCB will be keen to fully to utilise the loyal Bengaluru faithfuls on a track famously conducive to high scores.

VULNERABILITIES

The core of GT's batting remains largely unchanged from 2025, featuring the formidable top three of Shubman Gill, B. Sai Sudharsan, and Jos Buttler. While Glenn Phillips is a new addition, the departure of Sherfane Rutherford has left a void.

The issue? While Gill and Buttler have been scoring, the top order hasn't been as prolific as it was last year. With Sai Sudharsan struggling for rhythm at the top, the middle order has been forced into the game too early.

"The middle order was undoubtedly exposed," noted GT batting coach Matthew Hayden after the MI defeat. "We shouldn't be allowing players like Rahul Tewatia or Shahrukh Khan to face a high volume of deliveries. That's not their role; that's not what they train for."

'Shooting Has Just Started': Anurag Basu Reveals Kartik Aaryan And

Sree leela's

Film Still In Early Phase

Anurag Basu has addressed ongoing speculation surrounding his upcoming project starring Kartik Aaryan and Sreeleela, firmly debunking reports that suggested the film is already in production. The filmmaker revealed that the shoot is still in its early stages and far from completion.

In a conversation with Variety India, Anurag Basu opened up about the shoot and revealed that it is still in the early stages. He confirmed, "I've not shot more than 45 days for this film. The shooting has just started." The film is getting delayed because of various reasons too.

Kartik Aaryan And Sreeleela Shoot For Anurag Basu's Film In Srinagar

Kartik Aaryan and Sreeleela are currently in Srinagar, Jammu and Kashmir, busy shooting for their upcoming film directed by Anurag Basu. The project has generated a lot of buzz ever since it was officially announced in February last year. It is reportedly titled 'Tu Meri Zindagi Hai'. Recently, several pictures from the Kashmir schedule were recently leaked online. In once viral picture from the shoot, Kartik Aaryan, Sreeleela and Anurag Basu are seen having a conversation between takes. In another photo, the actress is seen wearing a blue top with matching ripped jeans and a red beanie. Kartik is also seen standing nearby with his hands in his pockets. He is seen sporting a rugged look with long hair and a full beard.

First Look Of Kartik Aaryan and Sreeleela's Film

The first look video of Anurag Basu's romantic musical was shared by Kartik Aaryan in February 2025. It opens with the crowd cheering, while the actor plays guitar and performs on stage. He is seen singing 'Tu Meri Zindagi Hai', sporting a brooding lover's look with a heavy beard and rugged long hair.

Yami Gautam

Learnt Quran For Haq, Reveals Director; Avinash Tiwary Says Marriage Deadline Is 2026-End

Filmmaker Suparn Verma has opened up about the preparation they did for his movie, Haq. Released in November 2025, the film stars Yami Gautam and Emraan Hashmi in the lead. It follows the story of Shazia Bano (played by Yami), the wife of a lawyer in 1970s India whose husband marries another woman. When he refuses to pay her maintenance, she drags him to court.After O'Romeo, Avinash Tiwary is gearing up for the release of Ginny Wedss Sunny 2 co-starring Medha Shankr. The film revolves around two individuals – a peppy Delhi girl and a shy small-town simpleton – and their families navigating the complexities of an arranged marriage. But is Avinash open to an arranged marriage?

Lokesh Kanagaraj's much-anticipated collaboration with Allu Arjun, tentatively titled AA23, is gaining momentum. Offering a fresh update on the project, the film's co-writer Rathna Kumar shared an update. He revealed that the groundwork for the film is progressing, with the team gearing up to begin shooting soon.

Anurag Basu has put all delay rumours to rest, confirming that his upcoming untitled film starring Kartik Aaryan and Sreeleela is progressing smoothly and remains on schedule for a theatrical release later this year.

Anne Hathaway is in the spotlight again after a new video from The Devil Wears Prada 2 promotions surfaced online. The clip is being discussed as it shows the actor accepting a Quran from a fan shortly after her recent "Inshallah" remark. This comes days after her use of the phrase during an interview had already sparked conversation.

Aryan Khan Fights To Keep Groom's Shoes, Nearly Falls In Viral Clip From BFF's Wedding

Aryan Khan was recently seen at a friend's wedding, where a video of him taking part in the traditional joota churai ritual has gone viral. The clip is being widely shared for the way the playful custom turned into a spirited moment during the ceremony.The video shows Aryan holding on to the groom's shoe and refusing to give it up, even as guests try to take it from him.

What is joota churai?

Joota churai is a common wedding tradition in many North Indian ceremonies. During the ritual, the bride's side tries to steal the groom's shoes while he is busy with wedding rituals. The groom's friends and family, on the other hand, try to protect the shoes. The game usually ends with a negotiation, where the groom's side pays money to get the shoes back. It is meant to be light-hearted and adds a playful break during the wedding.

What happened at the wedding

The video was shared by Zesst Events from the wedding of Rhea Nadkarni and Maahir Mehta. The planners mentioned that Maahir is Aryan Khan's best friend.They wrote, "When the Groom's best friend is the BA****S of Bollywood. Between sneaky steals, dramatic negotiations, and laughter echoing through every corner — this wasn't just joota churai, it was a total dhamaal."

Text on the video read: "Joota churai turned into a full-blown mini war!"In the clip, Aryan is seen in a casual outfit, holding the groom's shoe as others try to take it from him. At one point, he almost loses balance but still doesn't let go. He pulls back when people try to grab it and eventually runs off with the shoe.

Aryan Khan's recent work

Aryan Khan recently made his debut as a director with the Netflix series The Ba**ds of Bollywood. He served as the creator, writer, director, and showrunner for the project. The series starred a bouquet of stars including, Bobby Deol, Lakshya, Raghav Juyal, Mona Singh, and Sahher Bambba. It also included star cameo appearances by Shah Rukh Khan, Salman Khan, Aamir Khan, Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, and Diljit Dosanjh.

'Mat Kar': Twinkle Khanna Jokes About Akshay Kumar's 'Biggest' Contribution To Her writing Career

Twinkle Khanna spoke about her writing process and reading habits on the occasion of World Book Day. The actress-turned-author reflected on how her ideas take shape and how her personal experiences influence what she writes.

During the interaction, she also mentioned how her husband Akshay Kumar reacts to her work. She recalled, "This morning, I was discussing the topics I plan to touch upon in my next column, and he told me, 'Mat karna…do not get into that issue'. Mat kar is basically his only and biggest contribution to my writing career," she said.

Twinkle added that while her work may sometimes make people uncomfortable, her intention is not to provoke but to explore ideas. "My job is to make people reflect on the things that are visible. But our own conditioning blinds us to those factors. It might make people uncomfortable and they might call it offensive… (But) I think about how I will unravel the layers of conditioning not just around them but also around me because I also find my way through life as I write."She also spoke about her shift from acting to writing, noting that books have always been a constant in her life. "It is what I was able to give that medium, and books have always been my life and actually so has cinema," she said, adding that her experiences as a young actor also shaped her perspective.

Talking about her interest in language and literature, she said, "It comes a little bit from perhaps, my father (late veteran actor Rajesh Khanna), because I have a distinct memory when I was very young and I said, 'Will you pick me up from school? And he said, "Are you a pickup? I will fetch you from school.

That kind of just set my parameters of what language can do. And I grew up grew up in a family of readers. My sister (Rinkle Khanna) reads more than I do,"

Khanna also shared that she used to read more in her younger years. "Just keep doing what you're doing and finish the book you started when you were 18. I'm 52, and that one book I haven't been able to finish yet," she said, speaking about what she would tell her younger self.